



सोच और शब्द दोनों
ऐसे पुल हैं जो.
समझ में आ जाए
तो दूरी घटा देते हैं,
और ना समझ में
आये तो हमेशा के
लिये दूरी बढ़ा देते हैं.

मालवा हेराल्ड

न्यूज ब्रीफ

उत्तराखंड में एमएसएमई सेक्टर को मिलेगी नई उड़ान, निवेश और रोजगार में होगी वृद्धि



देहरादून/ जीएनएस। केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को मजबूती प्रदान करने और एमएसएमई को 'जैपियन' बनाने के उद्देश्य से 10 हजार करोड़ रुपये की

सहायता का प्रविधान किया गया है। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए उद्योग गया है। इससे अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड को अधिक लाभ मिलेगा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद राज्य में जो एक लाख करोड़ रुपये की ग्रांटी हुई है, इसमें 13 से 18 प्रतिशत एमएसएमई सेक्टर के उद्योग हैं। राज्य में 93887 एमएसएमई उद्योगों में 55.588 हजार करोड़ का निवेश हुआ और 4,60,070 लोग को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है। राज्य की जीडीपी में 13 प्रतिशत की हिस्सेदारी अकेले एमएसएमई की है। पहली राज्य होने के कारण राज्य सरकार के ज्यादातर नीतियां एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। यह क्षेत्र न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है, बल्कि औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति देने में भी अहम योगदान देता है। बजट में घोषित इस सहायता राशि से एमएसएमई इकाइयों को पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी। मोदी सरकार ने बजट में दो हजार करोड़ रुपये का टापअप भी प्रदान किया है, जिससे पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। इस टापअप से एमएसएमई सेक्टर को ऋण सुविधा, क्रेडिट गारंटी और वित्तीय सहायता से जुड़ी योजनाओं का अधिक लाभ मिल सकेगा। बजट में किया गया यह प्रविधान राज्य के एमएसएमई सेक्टर के विकास, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित बायोफार्मा शक्ति योजना उत्तराखंड जैसे फार्मा हब राज्य के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। बजट में अगले पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रविधान किया गया है।

एसआईआर पर बंगाल में रार, EC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता; दायर किया मुकदमा



कोलकाता/ जीएनएस। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाते हुए चुनाव आयोग व बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। ममता के सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात से ठीक एक दिन पहले इसका खुलासा हुआ है। मामले पर इसी सप्ताह सुनवाई की संभावना है। मालूम है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की खंडपीठ में आगामी बुधवार को बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी है।

ये मामले तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेक ओब्रायन व दोला सेन की ओर से किए गए हैं। वहीं कृष्णानगर से तृणमूल सांसद महंदा मोहंता की ओर से भी एक मामला दायर किया गया है। अब इस सूची में मुख्यमंत्री की ओर से किया गया मामला भी शामिल हो गया है। ममता ने आरोप लगाया है कि मानवीय पहलुओं की उम्मीद व नियम-कानूनों का उल्लंघन करके बंगाल के लोगों पर जबरन एसआईआर थोपा जा रहा है। ममता एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को छह बार पत्र भी लिख चुकी हैं।

रक्षा बजट में बढ़ोतरी, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम के निर्माण की संरचना



सिंदूर और पश्चिम एशिया में संघर्ष को देखते हुए एक अति महत्वपूर्ण, नीतिगत बदलाव देखने को मिला है। राजस्व व्यय जिसमें सेना के तीनों अंगों के वेतन भत्ते, पेंशन, संचालन और अन्य व्यय सम्मिलित हैं, को पिछले वर्ष के स्तर पर ही सीमित रखते हुए कैपिटल हेड में आवंटन में 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कैपिटल हेड के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि से सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण, साधन संपन्न बनाने हेतु तथा प्रौद्योगिकी प्रधान क्षमता के लिए अनुसंधान, स्वदेशीकरण एवं निर्माण को आगे विकसित करने तथा पूंजी अधिग्रहण, अनुसंधान और विकास के विभिन्न स्त्रोतों पर आपूर्ति और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

नई दिल्ली/ जीएनएस। वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष के 6.81 लाख करोड़ के आवंटन के मुकाबले इस वर्ष 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रक्षा बजट में कैपिटल हेड में 2.19 लाख करोड़ और 3.65 लाख करोड़ राजस्व खाते में राजस्व एवं वेतन व्यय हेतु एवं 1.71 लाख करोड़ रुपये पेंशन आदि के लिए आवंटित हैं। रक्षा बजट में उभरते भू-राजनीतिक जोखिमों व हालिया संचालन संबंधी जो संभावनाएं सामने आई हैं, खासकर ऑपरेशन

प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री का विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है केन्द्रीय बजट : मुख्यमंत्री

आर्थिक प्रगति को बढ़ाने, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप है बजट

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डेली कालेज इंदौर में केन्द्रीय बजट पर विषय-विशेषज्ञों से संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के बाद केन्द्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय बजट की सभी क्षेत्रों में सराहना हो रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टैक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है। इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश को भी विशेष लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री का अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान करने की व्यवस्था है। राजकोषीय घाटे का 4.3त्र का लक्ष्य रखा गया

है। राज्यों के लिए एक लाख 40 हजार करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है, जिससे मध्यप्रदेश को भी लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत को बायोफार्मा हब बनाया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का भी विकास होगा। केन्द्रीय बजट में केयर इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान देने के प्रावधान किए गए हैं। इससे बुजुर्गों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था होगी। गंभीर बीमारियों की दवाएं भी सस्ती होंगी, जिससे सभी वर्गों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय बजट में विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास करने का प्राथमिकता दी गई है, इससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ए.आई. के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त गाइड उपलब्ध कराने की व्यवस्था से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित स्थलों को खोलने के निर्णय से देश-विदेश के लोग हमारी समृद्ध प्राचीन विरासत से परिचित और प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों को टैक्स में दी गई राहत से वैश्विक स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट सबका साथ- सबका विकास की भावना के अनुरूप है।

छोटे, मझोले और धार्मिक शहरों का होगा कार्याकल्प, बनेंगे नए शहरी आर्थिक क्षेत्र

नई दिल्ली/ जीएनएस। शहरों में जिस तरह से आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है और 2030 तक देश की करीब 45 प्रतिशत आबादी के शहरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, उसके देखते हुए बजट में केंद्र सरकार ने छोटे, मझोले यानी टियर-2 व टियर-3 शहरों के साथ ही धार्मिक शहरों के कार्याकल्प और उसे विस्तार देने को लेकर बड़ी पहल की है। जिसमें ऐसे शहरों की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें नए शहरी आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा है।



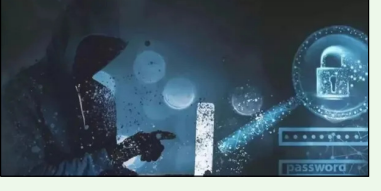
उन्हें पानी, सीवर, परिवहन जैसी जरूरी सुविधाओं से लैस करना है, जिससे वहां रहने वालों का जीवन आसान बन सके। साथ ही उसके आसपास आर्थिक गतिविधियां भी संचालित की जा सकें। बजट में किन बातों पर फोकस- वैसे भी

आर्थिक सर्वेक्षण में शहरों के विकास को सिर्फ अच्छे फुटपाथों से न मापते हुए उन्हें नागरिक केंद्रित विकास को गति देने की राह दिखाई गई थी। जिसमें नागरिक सुविधाओं के साथ उनके लिए अच्छे शैक्षणिक संस्थान और रोजगार के साधन भी होने चाहिए। बजट में शायद इसी दिशा में फोकस करते हुए ऐसे नए शहरी आर्थिक क्षेत्र बनाने की पहल की गई है, जिसमें कई छोटे और मझोले शहरों के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी विकसित किया जा सके। किन शहरों पर किया गया फोकस- इनमें वाणसी, उज्जैन व अयोध्या जैसे धार्मिक शहरों पर फोकस किया गया है, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उस लिहाज से उन्हें विस्तार देने व सुविधाओं को जुटाने पर

फोकस किया जाएगा। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक राज्यों की मदद से चैलेंज मोड में ऐसे शहरों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही उनके विकास व विस्तार की योजना बनाई जाएगी।

इस योजना के तहत चयनित शहरों की जमीनी स्तर पर पहले बदलाव दिखाना होगा, इसके बाद ही उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी। शहरी विकास मामले के विशेषज्ञ हिंसा वैध के मुताबिक यह पहल सोच के स्तर पर अच्छी है लेकिन इस शहरी आर्थिक क्षेत्र का प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा। व कैसे काम करेगा। इसे लेकर बजट में कोई राह नहीं दिखाई है। जबकि शहरी विकास के लिए जो सबसे जरूरी है वह प्रशासनिक ढांचा है, क्योंकि उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी।

कानपुर में कारोबारी से धोखाधड़ी, फर्जी रिटर्न फाइल कर 12.66 करोड़ की ठगी



चला कि शांति ने जीएस्टी पंजीयन खाते को हैक कर फोन नंबर और ईमेल आइडी बदले हैं। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रावतपुर के राधाबिहार निवासी कारोबारी उत्कर्ष सविता की फर्म आर्दविका ट्रेडर्स स्मार्ट मीटर लगाने का काम करती है। उत्कर्ष के मुताबिक उनके जीएस्टी पंजीयन से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल आइडी बदल कर किसी शांति ने उनके जीएस्टी खाते तक अनधिकृत पहुंच बना ली।

कानपुर/ जीएनएस। रावतपुर में एक कारोबारी के जीएस्टी खाते में सेंध लगाकर शांति ने 70.37 करोड़ से ज्यादा की फर्जी जीएस्टी रिटर्न फाइल कर 12.66 करोड़ की धोखाधड़ी कर डाली। कारोबारी के लागिण करने पर पता

आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता के घर में तोड़फोड़ और आगजनी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं

नई दिल्ली/ जीएनएस। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के इब्राहिमपट्टनम में रिविडिंग कारोबारियों के वाईएसआरसीपी के नेता और पूर्व मंत्री जोगी रमेश के घर में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। यह घटना वरिष्ठ वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू पर कथित जानलेवा हमले के एक दिन बाद सामने आई है। घटना के बाद इब्राहिमपट्टनम में कई



घंटों तक तनावपूर्ण हालात बने रहे। घटना की पुष्टि करते हुए पश्चिम जौन के सहायक पुलिस आयुक्त दुर्गा राव ने बताया कि फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी बीच, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने आरोप लगाया कि तोड़फोड़ के दौरान घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया गया और मकान को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके पहले तेलंगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबाती रामबाबू के घर के बाहर तोड़फोड़ की थी और गाड़ियों में आग लगा दी थी।

कंपनी के मैनेजर हिमंत सिंह नागर निवासी शिकायतकर्ता राजीव शर्मा ने पुलिस को बताया कि नितीश पाठक कंपनी में एजीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था और ऑनलाइन ऑर्डर की पैकिंग के दौरान धोखाधड़ी के मामले में कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने एक एजीक्यूटिव सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य दो आरोपित हीना और बेदी मेडिकोज फरार हैं।

16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट स्वीकार, राज्यों को हाथ लगी मायूसी; केंद्र के एक फैसले से क्या बदल जाएगा?

नई दिल्ली/ जीएनएस। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और राज्यों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से 41 प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश को बरकरार रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026-27 पेश करते हुए संसद में इस बात की जानकारी दी। वित्त मंत्री की घोषणा से निश्चित तौर पर इस बार केन्द्रीय राजस्व में ज्यादा हिस्सेदारी की उम्मीद लगाये राज्यों के ज्यादा मायूसी हाथ लगी होगी। खास तौर पर दक्षिण क्षेत्र के सत्ताधारी गैर-भाजपाई राज्यों को। इन राज्यों की तरफ से लगातार यह मांग उठ रही थी कि चूक देश के कुल आर्थिक विकास में उनका योगदान ज्यादा है, इसलिए उन्हें केन्द्रीय राजस्व में ज्यादा हिस्सेदारी की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

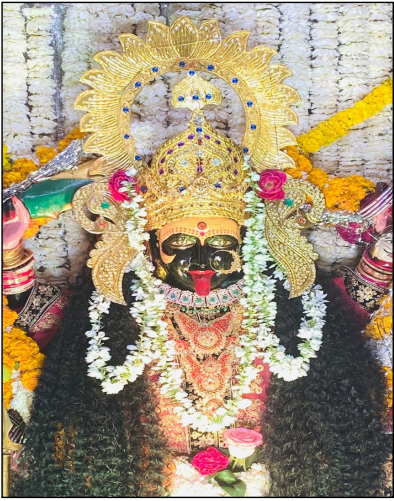


पनागढ़िया ने की थी। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षीय अवधि के लिए लागू होंगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, %वित्त आयोग ने 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत पोर्ट और उस पर कार्रवाई रिपोर्ट सदन पटल पर में रखी जा रही है। 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में 41 प्रतिशत हिस्सा बरकरार रखने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह 15वें वित्त आयोग की निरंतरता मे

है। साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये का वित्त आयोग अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान तथा आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल है। राजस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे राज्य-राज्यों को उक्त फैसले से निराशा हो लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारी इसे संतुलित और व्यावहारिक मान रहे हैं। कारण यह बताया जा रहा है कि केंद्र अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों (रक्षा, विदेश नीति, बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आदि) को ध्यान में रखते हुए भी राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराता है। साथ ही इससे अपना राजस्व तंत्र का विस्तार करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं होने वाले राज्य भी ज्यादा सतर्क होंगे और स्वयं का राजस्व बढ़ाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की आर्थिक प्रगति के साथ ही जीएस्टी संग्रह में भी लगातार वृद्धि होने की संभावना है, इससे भी राज्यों का हिस्सा लगातार बढ़ता रहेगा।

DIPL SINCE 1991
Innovative Design Superior Materials Exceptional Craftsmanship
देवशिल्प इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
No. 140, 1st Floor, सी-21, नानाखेडा, उज्जैन (म.प्र.)
होटल्स, बंगला, फॉर्म हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेन्ट, शॉप आदि बनवाने के लिए संपर्क करें।
What is the DIPL ?
हमारी खासियत क्या है ?
हम भारत के विभिन्न भागों में हमारी कम्पनी हर तरह का प्रोजेक्ट करती है। और हमारी हर जगह टीम तैयार रहती है। जैसे सिलिब परोकेट में हमारे पास सभी तरह के अनुभवी इंजीनियर और सुपरवाइजर टायर रहते हैं और भारत विभिन्न भागों में हम कार्य करते हैं और अभी हमारी सर्विस अबतिका नगरी उज्जैन में भी तैयार है मित्रों हम हर वकत तैयार रहते हैं।
जैसे कोनसेक्शन इटीरियर एक्सटीरियर
संतोष सोराष्ट्रीय
93031-92711
श्रीमती कृष्णा सुथार
99072-83928

श्री नवदुर्गा महाकाली माता मंदिर में भव्य महोत्सव, श्रद्धा और भक्ति से गुंजा परिसर



इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। श्री नवदुर्गा महाकाली माता मंदिर, नेहरू नगर, पाटनीपुरा में 1 फरवरी को वार्षिक महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मां भवती की असीम कृपा से आयोजित इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा।

महोत्सव के अवसर पर मंदिर को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया था। मां भवती का भव्य फूल बंगला, दिव्य श्रृंगार और विशेष महाअरती श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। सुबह से ही भक्तों की

लंबी कतारें देखने को मिलीं और श्रद्धालुओं ने पूरे आस्था भाव से मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की।

मंदिर के पुजारी पंडित श्री गिरिजान किशोर दुबे ने बताया कि मंदिर की स्थापना 1 फरवरी 2008 को हुई थी और इस वर्ष मंदिर ने अपने 17 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसी उपलक्ष्य में इस बार महोत्सव को विशेष रूप से भव्य स्वरूप दिया गया। उन्होंने कहा कि मां महाकाली एवं श्री नवदुर्गा माता की कृपा से यह आयोजन प्रतिवर्ष सफलतापूर्वक संपन्न होता आ रहा है।

महोत्सव के दौरान विधिवत पूजन, हवन, ध्यानाभ्यास एवं प्रसादी वितरण किया गया। महाअरती के समय पूरा वातावरण जय माता दी के जयघोष से गुंजा उठा, जिससे श्रद्धालु

भावविभोर हो गए। भक्तों में विशेष उत्साह और भक्ति भाव देखने को मिला।

मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन समाज में धार्मिक आस्था, एकता और सेवा भावना को मजबूत करते हैं। समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ।

अंत में आयोजक समिति ने सभी श्रद्धालुओं, सहयोगकर्ताओं और सेवाभावी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मां भवती के साथ महोत्सव आयोजित करने का संकल्प दोहराया।

सोशल मीडिया से रहे सावधान, जरा सी चूक बन सकती है परेशानी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सोशल मीडिया पर उतनी ही बातें शेयर करें जो जरूरी हैं। जीवन की हर छोटी से छोटी घटना या अपनी निजता को प्रदर्शित करना परेशानी का कारण बन सकता है। यह बात साइबर फ्राइड ब्रांच के उप निरीक्षक श्री शिवम ठाकुर ने न्यू लाइफ हार्ड सेकेटरी स्कूल न्यू मारुति नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित जागरूकता कार्यशाला में बच्चों को साइबर अपराध से किस तरह बचा जाता है और सोशल मीडिया के दुष्परिणाम की जानकारी देते हुए कही। कार्यक्रम में अभिभाषक तुकाराम

ठाकुर प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय इंदौर ने बच्चों को निशुल्क विधिक सहायता उनके अधिकार न्याय पाने की प्रक्रिया के साथ हेल्पलाइन 15100 की जानकारी दी। बाल विवाह विरोधी उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक ने बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी विवाह में शामिल होने से पहले वर वधु को उम्र को परखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम विवाह में शामिल होकर उसके साथी बन जाए और हम पर भी अपराध दर्ज हो। बच्चे अपने माता-पिता को अधिनियम की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास करें जिससे हमारा देश बाल विवाह

मुक्त बने। उड़न दस्ता सदस्य संगीता सिंह ने बच्चों को बताया कि उन्हें माता-पिता की बातों को मनाना चाहिए। कभी भी माता-पिता उनका बुरा नहीं चाहते, उनकी हर बात में कोई ना कोई सीख होती है। घर से निकले तो अनजान लोगों से बचें। उनके दिए जाने वाले प्रलोभन में ना जाए और खुद की सुरक्षा के लिए प्रयास करें। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से अपनी शिकायत पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाने की जानकारी भी दी। फिल्म निर्माता राजेंद्र राठौड़ ने बच्चों को नशा मुक्ति के महत्व को समझाते हुए बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा और भविष्य में इसका पढ़ने वाला प्रभाव समझाया।

कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इंदौर के सफल तीन साल, पेश की मरीज़-केन्द्रित उन्नत देखभाल की मिसाल



इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इंदौर ने आज अपनी सेवा के तीन साल पूरे किए। इन तीन सालों में इस अस्पताल ने नैतिक और मरीज़-केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी पहचान को और मजबूत किया है। अपने फुल-टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम के साथ, इस अस्पताल ने अलग-अलग विशेषज्ञताओं में अपनी मल्टी-डिस्प्लिनरी विशेषज्ञता के जरिए व्यापक देखभाल के लिए एक मजबूत भरोसा कायम किया है।

पिछले तीन सालों में, अस्पताल ने अपनी सुविधाओं को और बेहतर बनाया है। यहाँ मिनिमली इन्वेसिव सीएबीजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक इलाज की तकनीकों शुरू की गई हैं, जिन्हें लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और भरोसा मिला है।

जल्द ही अस्पताल में लिबर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू होने वाली है।

यह अस्पताल मध्य प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल है, जहाँ प्रोस्टेट के इलाज के लिए यूरो-लिफ्ट टेक्नोलॉजी, हार्निया की सर्जरी के लिए ई-टीपी टेक्निक और डबल बलून एन्टेरोस्कोपी जैसी उन्नत और हाई-एंड प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं। साथ ही, यह मध्य प्रदेश का पहला कॉर्पोरेट अस्पताल है जिसने एन्डोब्रोन्कोसकॉपी सुविधा शुरू

की है।

मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में रहने वाले मरीजों तक उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इंदौर ने कई शहरों में अपनी ओपीडी सेवाएँ शुरू की हैं। इनमें देवास, उज्जैन, धार, खंडवा, महू, गुना, मंदसौर, रतलमा, जवाहरपुर, सोनकच्छ और अहमदाबाद जैसे शहर शामिल हैं।

कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इंदौर ने कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, ऑर्थोपेडिक्स, रीनल साइंसेस और ट्रांसप्लांट के अपने सेंटर ऑफ़ एक्सर्सेस और अधिक मजबूत और विस्तृत किया है। अस्पताल ने मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के मरीजों के जटिल और उच्च जोखिम वाले मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया है।

केंद्रीय बजट विकास को देगा नई गति, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊंचे पायदान पर पहुंचाएगा : मुख्यमंत्री

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 विकास को और अधिक गति देने वाला है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर उच्च स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह बात भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम के दौरान कही, जहाँ उन्होंने प्रबुद्धजनों के साथ केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखा और बजट पर संवाद किया।

डेली कॉलेज स्थित डीसीबीएम हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री तुलसीराम सिलावट, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, महापौर पुष्पमित्र भागव, प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे, विधायक मालिनी गौड, महेंद्र हार्डिया सहित जनप्रतिनिधि, संपन्न पदाधिकारी और बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। इसके साथ ही शहर के सभी 35 मंडलों में भी बजट को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने वाला है। बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना पर आधारित है, जो आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनसामान्य की अपेक्षाओं को भी पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट में वस्त्र उद्योग क्षेत्र में रिफॉर्म के प्रावधानों से मध्यप्रदेश के कपड़ा उद्योग को

बड़ा लाभ मिलेगा। राज्यों के लिए एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास, शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर पांच वर्षों में 5000 करोड़ रुपये खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों के विकास, प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों के उन्नयन जैसे प्रावधानों से प्रदेश को व्यापक लाभ मिलेगा। इनकम टैक्स में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3 प्रतिशत रखा गया है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बजट में भारत को बायोफार्मा हब बनाने, क्लिनिकल ट्रायल स्थलों के विकास और केयर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, जिससे बुजुर्गों के इलाज की बेहतर व्यवस्था होगी और गंभीर बीमारियों की दवाएँ सस्ती होंगी। उन्होंने कहा कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की सौगात से मध्यप्रदेश में करीब तीन लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे और छह लाख किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे मालवा-निमाड़ अंचल औद्योगिक विकास की नई दिशा में आगे बढ़ेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्धजनों ने बजट को इंप्रोस्ट्रक्चर, रोजगार, एआई, ग्रीन एनर्जी, रिसेच एंड डेवलपमेंट और उद्योगों को गति देने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के संवाद कार्यक्रम बजट को जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं और देश व प्रदेश के विकास में सकारात्मक योगदान देंगे।

रोजगार मेला (युवा संगम) का आयोजन आज 2 फरवरी को

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। राज्य शासन के निर्देशानुसार इंदौर जिले में जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा आज 02 फरवरी को रोजगार मेला (युवा संगम कार्यक्रम) का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शासकीय महाविद्यालय गुरुकुल परिसर रंगवास रोड राऊ में प्रातः 10 बजे से 03 बजे तक सम्पन्न होगा। इस आयोजन का उद्देश्य एक ही छत के नीचे रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराना है। जिला रोजगार कार्यालय के उपसंचालक श्री पी.एस. मण्डलौड़ ने बताया कि उक्त रोजगार मेले में आवेदकों को करियर बनाने का सुनहरे अवसर के साथ-साथ स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये लोन की प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। साथ ही रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित कम्पनियाँ जैसे- तित्वा टेक्नोलॉजीज, आईसेक्ट, एस्पेके फार्नेस, फार्मा ग्रोथ, जस्ट डायल, ओशियन मोटर्स, मोजाईक प्रायवेट लिमिटेड, इंट्रस्टास कनेक्टर्स, थर्ड आई सिक्यूरिटी, मेडवॉलस, एस्कै-1 रिसेप्सिंस आदि के 500 से अधिक रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रारम्भिक रूप से चयन के लिए शामिल होंगे। ये कम्पनियाँ डिजिटल मार्केटिंग, साइट इंजीनियर, क्राइटीक इंजीनियर, रिसेप्सिंस, एच.आर., बैंक ऑफिस, कम्प्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिष्ट, सैल्स, बीपीओ, पैकेजिंग, हेल्पर, टेक्नीशियन जैसे-फिटर/टर्नर/मशीनिष्ट, वैल्डर आदि के विभिन्न पदों हेतु आकर्षक वेतन पर रोजगार प्रदान करने हेतु कम्पनियों के प्रतिनिधि आवेदकों के साक्षात्कार लेकर प्रारम्भिक रूप से चयन करेंगी। उक्त रोजगार मेले में 18 से 40 वर्ष के युवा शामिल हो सकते हैं। जिनकी शैक्षणिक योग्यता पाँचवीं/आठवीं/हाईस्कूल से लेकर स्नातकोत्तर बीई/बीटेक (सिविल/ मेकेनिकल/ इलेक्ट्रीकल) विषय में पास एवं तकनीकी योग्यता जैसे-आईटीआई/डिप्लोमा होना चाहिए। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाले युवा अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों एवं बायोडेटा की प्रतियाँ भी आवश्यक रूप से साथ लाना अनिवार्य है।

नर्मदा जयंती पर ओंकारेश्वर गया युवक मिला मृत, पुलिस के लिए मुखबिरी का संदेह

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नर्मदा जयंती के दिन ओंकारेश्वर गए इंदौर के एक युवक का शव शुक्रवार देर शाम नर्मदा नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के हाथ-पैर बंधे हुए थे, जिससे पुलिस ने मामला को हत्या मानते हुए जांच शुरू कर दी है।

नर्मदा जयंती पर गया था ओंकारेश्वर-मृतक की पहचान तिलक नगर था। क्षेत्र के पिपल्याहाना निवासी मनीष भट्ट के रूप में हुई है। मनीष नर्मदा जयंती के अवसर पर दोस्तों के साथ ओंकारेश्वर स्नान करने गया था, लेकिन इसके बाद घर वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा संपर्क किए जाने पर उसके दोस्तों ने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिवार ने मनीष की तलाश शुरू की, लेकिन वह किन दोस्तों के साथ ओंकारेश्वर गया था, इसकी स्पष्ट जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है।

भारत उदय का अर्थ अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव है प्रदीप जोशी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारत शोध और बोध की भूमि रहा है और इन दोनों का मूल आधार आध्यात्म है। आज जब भारत उदय की ओर अग्रसर है, तब उसका वास्तविक अर्थ समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। भारत का विकास तभी सार्थक होगा, जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित होगी। यह विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्री प्रदीप जोशी ने व्यक्त किए। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मुख्य सभागृह में आयोजित नर्मदा साहित्य मंथन के पांचवें आयाम के समापन सत्र को 'मंथन से प्रबोधन' विषय पर संबोधित कर रहे थे।



राजनीतिक ऑडिट पर लगातार चर्चा होती रहती है, वहीं समाज को सामाजिक ऑडिट की भी उतनी ही

आवश्यकता है। समाज में क्या अच्छा हो रहा है, कहां कमजोरियाँ हैं और इन स्थितियों में मेरी व्यक्तिगत भूमिका क्या है, इस पर गहराई से चिंतन होना चाहिए। भारत की सामाजिक व्यवस्था कभी भी सकारण आधारित नहीं रही, बल्कि यह समाज आधारित रही है, जहाँ समाज स्वयं अपने मुद्दों पर विचार करता था। समय के साथ समाज के मुद्दे बदले हैं, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में प्रबोधन नहीं होगा, तब तक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत के गौरवशाली अतीत से जुड़कर वर्तमान में अपनी भूमिका को समझना और उसी

आधार पर भविष्य की नींव रखना आवश्यक है। आज विश्व स्तर पर सभ्यता और आर्थिक ताकतों के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसमें भारत की भूमिका विशिष्ट है। समाज को इस विषय पर भी प्रबोधित करने की आवश्यकता है, ताकि भारत का पक्ष वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा जा सके। भारत में कुछ कमियाँ भी हैं, जिन्हें विचार और मंथन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम में पद्यश्री सम्मानित श्री सुशील दोशी ने कहा कि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है और देश को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने जीवन में नैतिक मूल्यों की गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन मूल्यों को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है।

विकसित भारत को समर्पित बजट, शहरों के विकास की रफ्तार और तेज होगी: महापौर

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर के महापौर श्री पुष्पमित्र भागव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी और समावेशी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के युवा, गरीब, किसान और महिलाओं के कल्याण को समर्पित है तथा इसके विभिन्न प्रावधानों से शहरों के विकास की रफ्तार और अधिक तेज होगी।

महापौर श्री भागव ने कहा कि भारत को वैश्विक जैव-फार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परियोजना के साथ बायो फार्मा शक्ति परियोजना की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। इससे जैविक और जैव-सदृश दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और



अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे तकनीक और कार्यकुशलता के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। महापौर ने कहा कि देश में बढ़ते रोग-भार, विशेषकर नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, कैंसर, हृदय, किडनी और लिबर संबंधी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का फोकस रोकथाम, स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज पर होना आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। यह मोदी सरकार की

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश और आगे बढ़ेगा।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के शुभारंभ को भी भविष्य के भारत के लिए निर्णायक पहल बताया। इस मिशन के माध्यम से तकनीकी एवं कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले

अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे तकनीक और कार्यकुशलता के क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। महापौर ने कहा कि देश में बढ़ते रोग-भार, विशेषकर नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, कैंसर, हृदय, किडनी और लिबर संबंधी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का फोकस रोकथाम, स्क्रीनिंग और शुरुआती इलाज पर होना आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। यह मोदी सरकार की

दूरदर्शी सोच और जागरूकता का परिणाम है। उन्होंने उच्च मूल्य वाले, प्रौद्योगिकी-उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरणों के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने की योजना को शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। अग्निशमन उपकरणों से लेकर लिफ्ट और सुरंग खोदने वाली मशीनों तक के निर्माण को बढ़ावा मिलने से विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों को ऐतिहासिक लाभ मिलेगा।

महापौर श्री भागव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र बन चुकी है। सरकार की नीतिगत फैसलों से नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचा है। विगत वित्तीय वर्ष में लगभग 7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, जिससे मध्य वर्ग का बाजार सशक्त हुआ है और गांवों तक आर्थिक सुधारों का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में बना है और इसके तीन प्रमुख कर्तव्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं-आर्थिक गति को बढ़ावा देना, निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत करना; जनता की

उम्मीदों को पूरा करते हुए सामान्य नागरिकों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर देना; तथा सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ शहरी और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस करना।

महापौर ने कहा कि घरेलू विनिर्माण क्षमता के निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और अनावश्यक आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। लोक-लुभावनवाद की बजाय आम लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कार्ययोजना के चलते मजबूत मैक्रो-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तेज औद्योगिकीकरण और शहरी विकास के लिए किए गए विशेष प्रावधानों से नगरीय जीवन के संसाधनों में ऐतिहासिक वृद्धि होगी। आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए यह केंद्रीय बजट देश को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक मजबूत आधार सिद्ध होगा।

आशाओं का बजट सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला, विकास की नई नींव रखेगा - श्रवण सिंह चावड़ा



इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नवें केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने बजट को आशाओं से भरा और दूरदर्शी बताते हुए इसकी सराहना की है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने कहा कि यह आशाओं का बजट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा, रेलवे और पर्यटन विकास पर विशेष फोकस किया गया है। यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखता है, बल्कि भविष्य की वित्तीय समृद्धि की भी मजबूत नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियाँ देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बजट को विकासोन्मुख और जनकल्याणकारी बताते हुए कहा कि इसमें किसान, युवा, महिलाएं, मध्यम वर्ग और व्यापारी सहित समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर दिया गया जोर देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा। श्रवण सिंह चावड़ा ने विश्वास जताया कि यह बजट देश को प्रगति के नए पथ पर ले जाने वाला साबित होगा।

केयर सीएचएल अस्पताल को अंतिम चेतानी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर के केयर सीएचएल चिकित्सालय को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतिम चेतानी देते हुए कहा गया है कि वे अस्पताल में मरीजों के भर्ती रहते हुए किसी भी तरह का निर्माण नहीं करें। मरीजों के भर्ती रहते निर्माण कार्य किये जाने से संक्रमण फैलने और दुर्घटना की आशंका रहती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि केयर सीएचएल चिकित्सालय के परिसर में अनाधिकृत अतिक्रमण किए जाने की शिकायत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम से उत्तर देने के लिए निर्देशित किया गया था, किंतु केयर सीएचएल अस्पताल ने उत्तर देने के लिए 15 दिवस का समय मांगा था।

केंद्र के आम बजट पर मंदसौर के भाजपा नेताओं ने कहा गुड तो कांग्रेस नेताओं ने कहा बेड

पक्ष, विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया, आम जनता ने कहा हितार्थ हो बजट



मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आम बजट पर मंदसौर के भाजपा नेताओं ने गुड प्रतिक्रिया दी तो कांग्रेस नेताओं ने बेड प्रतिक्रिया दी है। पक्ष, विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जा रही है। उधर, आम जनता ने कहा है कि जो भी तो बजट आम जनता के हितार्थ वाला हो

कलेक्टर श्री अर्थव्यवस्था को गति और रोजगार को बढ़ावा देने वाला- सांसद सुधीर गुप्ता- बजट भारत की अर्थव्यवस्था को गति और रोजगार को बढ़ावा देने वाला है। 53 लाख करोड़ का बजट देश की आर्थिक प्रगति का मापदंड है और सभी वर्गों के सपनों को पूंज लगाने वाला है, जिसकी भावना है-सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास और सबका ध्यास। उक्त बात सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर कही। सांसद गुप्ता ने बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री सीतारामण का अभार जताया। सांसद गुप्ता ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट में विकसित भारत

2047 की स्पष्ट झलक दिखाई देती है और यह आने वाले वर्षों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा। यह 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की सोच के साथ लाया गया बजट है। किसान, नौजवान, महिलाएं, शिक्षक, चिकित्सक और व्यापारी समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसे इस बजट में नजरअंदाज किया गया हो। उन्होंने कहा कि टैक्स प्रक्रियाओं का सरलीकरण मध्यम वर्ग के लिए राहतकारी है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष आवंटन और एमएसएमई के लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करेगा।

2047 के लक्ष्य पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बजट - सांसद बंशीलाल गुर्जर - केन्द्रीय बजट के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिये - मत्स्य पालन के लिये 500 जलाशयों व अमृत सरोवरों के निर्माण की पहल एवं मत्स्य उत्पादन एफ.पी.ओ. एवं महिला समूहों को बाजार से जोड़ने का प्रावधान। पशुपालन क्षेत्र में सब्सिडी - पशुधन उद्यमों को

संवर्धन और उनके आधुनिकीकरण के लिये तथा मुल्य निर्मित करने के लिये पशुधन, पानकों, उत्पादकों के एफ. पी. ओ. को प्रोत्साहन का प्रावधान है। नारियल उत्पादक किसानों के एक करोड़ और परिवार सहित 3 करोड़ नारियल उत्पादकों के लिये नारियल संवर्धन योजना की पहल सगहनिय एवं स्वागत योग्य है। पुराने कम उपज वाले फूलोधानों के संरक्षण पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, बादाम, और खुमानी की पौदावार बढ़ाने के लिये मुख्य संवर्धन, योजना का प्रावधान है। इस बजट में 12.00 लाख करोड़ से अधिक राशी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये रखी गई है इससे देश आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिये हर जिले में छात्रावास निर्माण की पहल महत्वपूर्ण है। नागरिकों के स्वास्थ्य की बेहतरि के लिये भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण के रूप में विकसित करने के लिये दस हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय बजट गाँव, गरीब, किसान और ग्रामीण भारत की खुली उपेक्षा-जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुर्जर- जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने संसद में पेश केंद्रीय बजट को गाँव, गरीब, किसान और मजदूर विरोधी बताते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह बजट पहली बार ऐसा है जिसमें किसान का नाम तक नहीं लिया गया - न सिंचाई पर कोई नई घोषणा, न खाद-बीज सब्सिडी में वृद्धि, न खेतीहर मजदूरों के लिए कोई राहत, और न ही रूकक की कानूनी गारंटी वा फसल बीमा में सुधार। गुर्जर ने कहा, यह चूक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक घोषणा है। मोदी सरकार ने अन्नदाता को भुला दिया है। बजट में, टूट, टूट, हड़-वैल्यू क्रॉस जैसे चमकदार नारों के पीछे छिपाकर किसानों के असल मुद्दों

बढ़ती खेती की लागत, गिरते फसल दाम, कर्ज का बोझ और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या डू से मुह मोड़ लिया गया है। जबकि इंधन और बड़े कॉरपोरेट्स को लाखों करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार तुरंत किसानों की सुनवाई करे, रूकक को कानूनी गारंटी दे, खाद-बीज पर सब्सिडी बढ़ाए और बजट में असल राहत शामिल करे।

बजट में व्यापारी वर्ग को कोई राहत नहीं - ल रातड़िया- जिला कांग्रेस अध्यक्ष उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ मंदसौर निर्विकार रातड़िया ने कहा कि केंद्रीय बजट से देश के व्यापारियों को बहुत उम्मीदें थी कि मंदी को झेल रहे व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नया बजट में होगा लेकिन जैसा कि हर बार होता है इस बार भाजपा की वित्त मंत्री ने वहीं किया सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। केन्द्रीय बजट के आने के तुरंत बाद शेयर बाजार धराशायी हो गई संसेक्स 1500 अंकों कि गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे स्पष्ट होता कि देश के शेयर बाजार ने भी बजट को स्वीकार नहीं किया है। बजट में कृषि, बेरोजगारी, शिक्षा पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इस बार तो बजट में मेडिकल कॉलेज वा आईआईटी, आईआईएम जैसे शैक्षणिक संस्थान बढ़ाने के बारे में कोई बजट नहीं दिया है। हर बार की तरह इस बार भी बजट में कहा गया है कि भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रु. का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनेगा लेकिन इस प्रकार की सिर्फ घोषणाएँ की जाती हैं उद्यमियों को इसका सीधा लाभ कभी नहीं मिलता। कुल मिलाकर इस बजट से सभी को निराशा ही मिली है पुराने बजट को उपर नीचे कर नये फोल्डर में लेकर पेश कर दिया गया है।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न, कलेक्टर 8 दिवस बाद पुनः करेंगे उपलब्धियों की समीक्षा



शिवपुरी/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक गतदिवस कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

कलेक्टर श्री चौधरी ने गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के आकड़ों में पाए गए अंतर को आपसी समन्वय से शीघ्र समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रभावी प्रबंधन, टीबी रोगियों की एक्स-रे जांच में वृद्धि, आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा एनआरसी में बच्चों के शत-प्रतिशत भर्ती किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा विभागीय उपलब्धियों की पुनः समीक्षा 8 दिवस बाद किए जाने की जानकारी दी गई।

बैठक में टीबी रोगियों की एक्स-रे जांच, एनआरसी में भर्ती बच्चों की स्थिति, गर्भवती महिलाओं की चार एनसी जांच, एनीमिया प्रबंधन, आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता, मातृ एवं शिशु मृत्यु, एचडब्ल्यूसी, आयुष्मान कार्ड, एनसीडी एवं टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री चौधरी ने एफसीएम इंजेक्शन की उपलब्धि कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मध्यम एवं गंभीर एनीमिया के प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए। एनसीडी पंजीयन में कम प्रगति वाले क्षेत्र बदरवास के बीसीएम एवं सुपरवाइजर को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने आयुष्मान आरोग्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता का औसत निकालकर दो दिवस में शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम: उपमुख्यमंत्री श्री देवड़ा

तेजी से आगे बढ़ते मध्यप्रदेश को मिलेगा विशेष लाभ

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड।

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने मध्यप्रदेश के नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण को कोटि-कोटि बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यप्रदेश जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेज गति से अपनी जीडीपी में बढ़ोतरी कर रहा है। पूंजीगत व्यय में हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। अब कैपेक्स बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया है। केन्द्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिये राज्यों को विशेष पूंजीगत सहायता योजना में 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। जो वित्त वर्ष से 50 हजार करोड़ रुपये अधिक है। इस योजना में मध्यप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना होगी। इससे अधोसंरचनात्मक गतिविधियों को विस्तार देने में भी मदद मिलेगी। अन्य राज्यों की तुलना में म.प्र. में एमएसएमई विकास का सबसे अच्छा इको-सिस्टम बना है। इस बजट से एमएसएमई सेक्टर को भरपूर विस्तार मिलेगा। उन्होंने कहा कि



देवड़ा ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट सबका साथ-सबका विकास की भावना के अनुरूप है। बायोफार्मा हब बनाने की पहल के दूरगामी परिणाम आएंगे। विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास किया जायेगा। लखपति दीदी विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की पहल स्वागत योग्य है। इसके तहत सेल्फ हेल्थ एंटरप्रेन्योर मार्ट बनाए जाएंगे जो क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के अंतर्गत सामुदायिक खुदरा आउटलेट्स के रूप में भी कार्य करेंगे। इससे मध्यप्रदेश में महिला उद्यमिता को भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है इसका लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में उभरते समीकंडक्टर सेक्टर को बजट से सपोर्ट

बजट में गरीब, युवा अन्नदाता और नारी शक्ति वर्ग पर विशेष फोकस है। उन्होंने कहा बजट में जिन तीन प्रमुख कर्तव्यों का उल्लेख है म.प्र. उनका पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है।

आर्थिक वृद्धि, जन आकांक्षाओं का सम्मान और सबका साथ सबका विकास बजट की विशेषताएं बताते हुए श्री

देवड़ा ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट सबका साथ-सबका विकास की भावना के अनुरूप है। बायोफार्मा हब बनाने की पहल के दूरगामी परिणाम आएंगे। विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास किया जायेगा। लखपति दीदी विस्तार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की पहल स्वागत योग्य है। इसके तहत सेल्फ हेल्थ एंटरप्रेन्योर मार्ट बनाए जाएंगे जो क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के अंतर्गत सामुदायिक खुदरा आउटलेट्स के रूप में भी कार्य करेंगे। इससे मध्यप्रदेश में महिला उद्यमिता को भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है इसका लाभ मध्यप्रदेश को मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में उभरते समीकंडक्टर सेक्टर को बजट से सपोर्ट

मिलेगा। वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफार्म से राज्य को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों का विकास किया जायेगा। शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5 हजार करोड़ खर्च किये जायेंगे। छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित होने से छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ केयर इकोसिस्टम पर विशेष जोर दिया गया है। जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जायेगा। जिससे बुजुर्गों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी जिससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास का निर्माण करने की अनूठी पहल बजट में की गई है। भारत को ग्लोबल मेन्स्युफैक्चरिंग हब बनाने की पहल से मध्यप्रदेश जैसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों को भी लाभ होगा। मध्यप्रदेश पर्यटन की संभावना से भरपूर राज्य है इसलिए केंद्रीय बजट में पर्यटन विकास संबंधी प्रस्ताव स्वागत योग्य है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार करोड़ खर्च जायेंगे, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा, कि इनकम टैक्स में छोटे करदाताओं के लिये प्रक्रिया आसान होगी। राजकोषिय घाटे का 4.3 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कुल 53 लाख 47 हजार करोड़ का बजट में पूंजीगत व्यय का अनुमान 12 लाख 21 हजार करोड़ रखा गया है। जी.डी.पी के लिये 393 लाख करोड़ का अनुमान रखा गया है जो विगत वर्ष की जी.डी.पी के अनुमान से 10 प्रतिशत अधिक है। इससे सभी राज्य जीडीपी में अपना योगदान बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

गुणवत्ता के साथ समय पर पूरी करें जलापूर्ति योजना- कलेक्टर

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक संपन्न

शिवपुरी/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में विधायक पोहरी कैलाश कुशवाहा, जिला पंचायत की अध्यक्ष नेहा यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज, समिति के सदस्य, पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री चौधरी ने बैठक में जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासामक योजनाओं की कार्य प्रगति की बारी-बारी समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पानी पहुंचे, इस प्रकार तीव्र गति से कार्य करें अधिकारी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थल जहां पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, उन्हें चिन्हित करें। हैंडपंप की सही समय पर शासन से मांग की जाए, जिससे ग्रामीण अंचलों में पानी की परेशानी



न आए। नल जल योजना बिजली के कारण प्रभावित न हो, अधिकारी इस बात का ध्यान रखें। जलापूर्ति योजनाओं की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने व जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पेयजल समस्या के निराकरण और जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।

पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत कुल स्वीकृत 1262 योजनाओं में से 536 योजनाओं का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कर एकल नलजल योजना में ग्रांडेंड वाटर दिया जा

रहा है जबकि शेष योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा 307 ग्राम में जल निगम के द्वारा वाटर दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है। एक ग्राम योजना के तहत जिले के 59 ग्रामों में लगभग 15 फरवरी तक पूरी तरह से जल पहुंचाया जाएगा।

जल निगम के अधिकारी ने बताया कि मड़ोखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना में शेष रहा इटकेबेल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक आ गया है, टैरिंजर करना अभी बाकी है। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट से टैरिंजर के दौरान जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। 289 टर्कियों का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बसई-2 समूह जल प्रदाय योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि इटकेबेल का कार्य हो चुका है, ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण कर टैरिंजर करना है। उन्होंने महोदय समूह योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि 75 प्रतिशत ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य मार्च तक पूर्ण हो जाएगा और इन योजनाओं से जल्द से जल्द संबंधित गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

उज्जैन में मंदसौर के निशानेबाजों का दबदबा: अंतर-वलब शूटिंग प्रतियोगिता में जीते 9 पदक



मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। उज्जैन में 30 और 31 जनवरी को संपन्न हुई तृतीय अंतर-क्लब राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में मंदसौर के खिलाड़ियों ने अपनी अचूक निशानेबाजी का लोहा मनवाया है। इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में नियुद्ध एयरान शूटिंग एवं आर्चरी स्पোর্ट्स एसोसिएशन, मंदसौर के 9 होनहार निशानेबाजों ने विभिन्न आयु वर्ग में पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया है। प्रतियोगिता में उज्जैन संभाग के कई प्रतिष्ठित क्लबों और एसोसिएशनों ने भाग लिया था। कड़े संघर्ष के बीच मंदसौर के

खिलाड़ियों ने शानदार एकाग्रता दिखाते हुए कुल 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में लखन सेन, अर्पण भंडारी, सान्वी कालरा एवं विशाल धनगर ने स्वर्ण पदक जीता वहीं डिना हर्तलिया, यशवर्धन चौहान, हिमाद्री सोनी एवं अर्पित सुथार ने रजत पदक व वर्षा सेन ने कांस्य पदक जीता। खिलाड़ियों की इस उल्लेख उपलब्धि पर वल्लुड नियुद्ध फेडरेशन के संस्थापक डॉ. नियुद्धाचार्य नरेन्द्र श्रीवास्तव, नियुद्ध एयरान एवं आर्चरी स्पোর্ट्स एसोसिएशन मंदसौर के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र अग्रवाल, एवं जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी श्री विजेन्द्र देवड़ा ने प्रसन्नता की। साथ ही, वल्लुड नियुद्ध फेडरेशन के वरिष्ठ प्रशिक्षक ए एवं एसोसिएशन के मुख्य प्रशिक्षक (कोच) नियुद्ध गुरु प्रवीण भंडारी, नियुद्ध गुरु अजय सिंह चौहान सहित प्रशिक्षक सत्री घोडेल, आदित्य सुरा, मनीष रैकवार, नयन्सी गंगवाल, अश्विनी भंडारी, वशिष्ठा श्रीवास्तव एवं हर्षिता सिसोदिया तथा एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने सभी विजेताओं के उज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी की समन्वय समिति बैठक सफलता पूर्वक सम्पन्न



मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर गहन चर्चा हुई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह-प्रभारी श्री संजय दत्त तथा जिला प्रभारी श्री मनोज राजानी ने विशेष रूप से भाग लिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह बैठक एकता, समर्पण और संगठन की ताकत का जीता-जागता उदाहरण है। श्री संजय दत्त और श्री मनोज राजानी के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न स्तरों पर संगठन सुजन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, जन-समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और आगामी चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर विस्तृत मंथन हुआ। श्री गुर्जर ने बताया कि बैठक में ब्लॉक स्तर के अध्यक्षों, प्रकोष्ठ और अन्य पदाधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, जन-आंदोलनों को गति देने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। सभी ने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। श्री संजय दत्त जी ने बैठक को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती पर बल दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के लिए जिला स्तर पर ऐसे समन्वय और सक्रियता आवश्यक है। श्री मनोज राजानी ने भी जिले की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। यह बैठक संगठन सुजन अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पार्टी को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बैठक में विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, विधानसभा प्रभारी राजेश भरावा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया, मंजीत सिंह टुटेजा, विधानसभा पूर्व प्रत्याक्षी परशुराम सिसोदिया, राकेश पाटीदार, प्रदेश पदाधिकारी राजेश रघुवंशी, सोमिल नाहटा, ओम सिंह भाटी, ब्लॉक अध्यक्षगण जगदीश धनगर, वीरेंद्र सिंह हाड, विकास दशोग, गोपाल विश्वकर्मा, सुश्री इश्र भाचावत, विनोद शर्मा, विजेश मालेचा, राहुल जैन, किशोर सिंह पंवार, हनुमंत सिंह राठौर, नया प्रेक्षक श्रीमती रश्मि पयामी, मोर्चा संगठन में दिलीप देवड़ा, गुंशी सिंह पटेल, रितिक पटेल, संदीप सलोदा, अनीस मंसूरी, ललित चंदेल, राजेंद्र सेठिया, दीपक पोखवाल आदि इस बैठक में मुख्यरूप सभी सदस्य उपस्थित रहे।

राजस्थान के राज्यपाल ने नरेंद्र अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया सम्मानित



मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा भारतीय पत्रकारिता स्थापना दिवस के उपलक्ष में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री हरीभाऊ किशनराव बागडे के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस समारोह के विशिष्ट अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री व.च.पटेल देवनाजी थे। च अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जैन ने की व मध्य प्रदेश विधानसभा श्री ओपी जोशी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह में देश भर के चुनिंदा पत्रकारों एवं समाजसेवा सहित अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर पत्रकार एवं समाजसेवी श्री नरेंद्र अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अग्रवाल के साथ अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए नेशनल मीडिया फाउंडेशन के प्रदेश सचिव श्री संजय वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजेंद्र चाणू एवं श्री सुनील भटनारिया ने महामहिम राज्यपाल एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनाजी को भगवान पशुपतिनाथ की तस्वीर भेंटकर मंदसौर आने का न्यौता भी दिया। महामहिम राज्यपाल ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ तो भी चल रहा है कुछ तो भी लिख रहे हैं वह ठीक नहीं है लेकिन व्यक्ति सम्मूहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर में कुछ भी कर सकता हूँ व हर काम की मान मर्यादा होती है।

विशानित संस्थान द्वारा प्रकृति योग संगीत त्रिवेणी संगम का दिव्य आयोजन

रतलाम/ प्रवीण व्यास/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पी ओ डूंडा श्री अरुण पाठक ने बताया कि नार की हृदय स्थली गुलाब चक्र स्थित विशानित योग संगीत संस्थान के विशाल कुमार वर्मा नित्येन्द्र आचार्य द्वारा भारत के नक्शा प्रदर्शित कर मूल में गुलाब चक्र की अनुपम छवि लिए प्रकृति योग संगीत त्रिवेणी संगम का समिन्ध्रित आयोजन किया गया।



यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021, स्क्र. इंडिया 2018 क्रोन आफ ग्लेवेलसी 2022 विशेष तौर पर उपस्थित होकर सुधुमर गीत प्रस्तुत किया व प्रतिभाओं को सम्मानित कर विचार व्यक्त करते हुए रतलाम जिला

प्रशासन जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा मंच प्रदान करने नगर की संस्थाओं द्वारा नव प्रतिभाओं को अवसर देना एक श्रेष्ठतम उपहार है ऐसे प्रयास प्रेरणादायी के कोशलाता में निरखार लाते हैं।

विशेष अतिथि स्वरूप वरिष्ठ समाजसेवी प्रकाश चंद्र व्यास पतंजलि युवा भारत राज्य प्रभारी प्रेम पुनिया, महावीर इंटरकांटिनेंटल

वन स्टॉप सेन्टर सखी ने सार्थक किया महिला की सुरक्षा व सम्मान

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं एडीएम श्री बी.एस.कलेश के निर्देशन में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वन स्टॉप सेन्टर (सखी) नीमच का संचालन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अंकिता पंड्या ने बताया, कि महिला (परिवर्तित नाम) मनीषा को विवाह के 15 वर्ष पश्चात संतान की प्राप्ति हुई। प्रसव के समय महिला के मस्तिष्क की कोई नस दब गई, जिससे उसके मस्तिष्क में रक्त का थक्का जमने लगा और ट्यूमर को निकालने के लिये महिला के सिर का ऑपरेशन करवाया, तो चेकअप के लिये परिवर्तित नाम हरीश (पति), मनीषा को लेकर अहमदाबाद गया मनीषा ऑपरेशन के पश्चात चीजें, व्यक्ति भूलने लगी, चेकअप के

बाद अहमदाबाद में मंदसौर वापस लौटते समय एक होटल पर शौच करने बस से उतरी और बड़ हरीश से बिछड़ गई। वहाँ से गुमशुदा हो गई। मनीषा अंधेरे में गलत रास्ते पर चली गई। हरीश व उसके परिजनों द्वारा मनीषा को बहुत ढूँढ परन्तु मनीषा नहीं मिली, तो हरीश व उसके परिजनों ने मनीषा के गुमशुदा होने की खबर सोशल मीडिया और पुलिस थाना मंदसौर में की। मनीषा नीमच शहर में भटकते हुए पुलिस प्रशासन को मिली तो महिला मनीषा को सुरक्षा की दृष्टि से वन स्टॉप सेन्टर नीमच के अस्थाई आश्रय में रखा गया।

महिला मनीषा को वन स्टॉप सेन्टर सखी से परामर्श सहायता, आश्रय सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता दी गई। मनीषा ने

काउंसलर द्वारा घटना के संबंध में पूछे जाने पर कुछ भी बता पाने में असमर्थता जताई। वन स्टॉप सेन्टर सखी की प्रभारी प्रशासक श्रीमती दिपिका नामदेव एवं उनकी टीम व पुलिस प्रशासन के सहयोग से महिला मनीषा के परिवार का पता लगाया गया व महिला मनीषा के सुरक्षित वन स्टॉप सेन्टर सखी नीमच में होने की सूचना दी और उन्हें नीमच बुलाया। एडीएम के आदेश पश्चात महिला मनीषा को केंद्र पुलिस नीमच के सुर्पद किया गया। ताकि महिला मनीषा के भाई राहुल की शिनाक के पश्चात मनीषा को उसके भाई राहुल के सुर्पद किया जा सके। इस तरह वन स्टॉप सेन्टर सखी ने अपने उद्देश्य महिला की सुरक्षा व सम्मान को सार्थक किया है।

सम्पादकीय विकसित भारत की उड़ान: बजट 2026 के आर्थिक संकल्प

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नवीन केंद्रीय बजट को यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2०47' के स्वप्न की ठोस आधारशिला के रूप में सामने आता है। यह बजट उस रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह है जो बीते वर्षों में चली आर्थिक सुधारों की पटरियों पर तेज़ गति से दौड़ते हुए अब भारत को उच्च विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की नई ऊँचाइयों की ओर ले जाने का दावा करता है। तुलनात्मक, विवेचनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि से यह बजट पूर्ववर्ती बजटों की निरंतरता को बनाए रखते हुए कई नए आयाम भी जोड़ता है, जो इसे ऐतिहासिक और भविष्यगामी बनाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। जहां पूर्व बजटों में संकट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को संभालने पर अधिक जोर था, वहीं यह बजट विकास की ऊंची उड़ान के लिए रनवे तैयार करता दिखाता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का मंत्र यहां नरे से आगे बढ़कर नीतिगत संरचना का रूप लेता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की दृष्टि विशेष रूप से विवेचनात्मक है। चिकित्सा अवसंरचना के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से गांव-गांव तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में किए गए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार स्वास्थ्य को केवल खर्च नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश मान रही है। यदि पिछले दशक के बजटों से तुलना की जाए तो स्वास्थ्य पर आवंटन और दृष्टिकोण दोनों में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यह बदलाव भारत को न केवल स्वस्थ समाज की ओर ले जाने वाला है, बल्कि उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को भी दीर्घकाल में मजबूती देगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट की आत्मा दूरदर्शी है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उपरती तकनीकों से जुड़ी शिक्षा पर बल यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य के भारत के लिए आज के युवाओं को तैयार करना चाहती है। पूर्ववर्ती बजटों में शिक्षा पर खर्च की चर्चा होती थी, लेकिन इस बजट में शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ यह बजट तुलनात्मक रूप से अधिक परिपक्व और व्यावहारिक प्रतीत होता है। विकास की दृष्टि से यह बजट 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस समावेशन' का मॉडल प्रस्तुत करता है। रेलवे कॉरिडोरों के विकास, लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने, सड़क, बंदरागह और शहरी अवसंरचना में निवेश को जिस तरह प्राथमिकता दी गई है, वह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सात रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन का माध्यम है। यदि इसे पिछले बजटों से जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार अब बुनियादी ढांचे को विकास का इंजन मानकर लगातार गति दे रही है। ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट विशेष उल्लेख के योग्य है। कृषि, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, किसान कल्याण और ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े प्रावधान यह संकेत देते हैं कि गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मंशा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। मेडिकल सुविधाओं, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता सुधरने की संभावना बढ़ती है। यह आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें गांव मजबूत होंगे तो देश स्वतः मजबूत होगा।। नारी शक्ति के सशक्तिकरण के संदर्भ में भी बजट का दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से व्यापक है। महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विशेष प्रावधान यह दर्शाते हैं कि महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। गरीबों और वंचित वर्गों के लिए लक्षित योजनाएं इस बजट को सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी संतुलित बनाती हैं। समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो यह बजट कल्याण और विकास के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है, जो किसी भी दीर्घकालिक आर्थिक नीति की अनिवार्य शर्त है। युवाओं के लिए यह बजट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप, नवाचार, स्किल डेव्लप, रोजगार सृजन और नई तकनीकों में निवेश युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। यदि इसे आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यह भी स्पष्ट होता है कि बजट में क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक यथार्थ का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि आलोचक इसे चुनावी बजट कह सकते हैं, लेकिन विवेचनात्मक दृष्टि से यह कहना अधिक उचित होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट का जन-आकांक्षाओं से जुड़ा होना स्वाभाविक है।

जीवन की जटिलताओं को आसान बनाता है - सहज योग



जीवन है तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, यही उतार चढ़ाव जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। कभी कहीं कोई बाधा आये तो उस बाधा से निकलने का दौर सकारात्मक दृष्टिकोण वालों के लिए रोमांचक होता है और बाधा से मुक्त होते ही मिलती है आत्मिक संतुष्टि और जीतने की खुशी। परंतु सत्य तो यह है कि जीवन में आने वाली इन जटिलताओं को सहजता से लेना तभी संभव होगा जब हम संतुलन में हों। जरा सी तकलीफ़ होते ही घबरा जाने की प्रवृत्ति हमारी परेशानों को और बढ़ा देती है फलस्वरूप समस्या का समाधान मिलना मुश्किल हो जाता है। आज के दौर में जब समाज व विश्व में अशांति की स्थिति बनी हुई है तब इन सबसे तटस्थ रह पाना मुश्किल हो जाता है। पर, हमें समाज और विश्व की समस्याओं पर विचार करते हुए भी, उन समस्याओं का हिस्सा होते हुये भी मनस्थिति पर काबू पाने का गुर आना चाहिए। यह आज के दौर की आवश्यकता है। यदि हम स्वयं पर काबू नहीं रख पाते हैं तो स्वयं भी दुखी रहेंगे और परिवार को भी नहीं संभाल पायेंगे। परिवार के सभी सदस्यों को सहज योग विधा को सीखना चाहिए ताकि जीवन के हर पड़ाव पर शांति से रह सकें। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि परमात्मा का निवास हमारे अंदर है पर इसका अनुभव नहीं कर पाने से वे असमंजस की स्थिति में रहते हैं। सहज योग की संस्थापिका परम पूज्य श्री माताजी निमल देवी ने कुल्लुनी जगरण और ध्यान योग की इस विधा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और साधकों को आत्मसाक्षात्कार देकर अपने अंदर की अंधी अंधकार शक्ति का आभास कराया। आज लाखों लोग सहज योग के माध्यम से ध्यान करते हुये निश्चिन्त शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। 24 सितंबर 1995 के प्रवचन में श्री माताजी ने कहा कि सहज योग से ये सभी छोटी-छोटी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। लेकिन एक बात यह है कि आपको एक व्यक्ति के रूप में एकजुट होकर काम करना चाहिए, एक संघ का अभिन्न अंग। और यह भी समझने की कोशिश करें कि आप अपनी समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं... ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं क्योंकि अब आप आत्मसाक्षात्कारी आत्मा हैं क्योंकि ईश्वर की मदद है और साथ ही आप खुद भी बहुत सतर्क हो गए हैं। संघ से श्री माताजी का तात्पर्य सहज योग की सामूहिकता से है। भारत व विदेशों में भी किये गये चिकित्सा शोध ने यह दर्शाया है कि सहज योग के माध्यम से शारीरिक और मनोदैहिक रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। हम परमात्मा से जुड़े बिना अपने जीवन का अर्थ नहीं जान सकते हैं। जैसे ही हमें अपने जीवन का अर्थ समझ में आ जायेगा, हमारे जीवन में पूर्णकालिक वसंत का प्रवेश हो जायेगा। हर जटिलता को सही समाधान मिलेगा।

अमेरिका द्वारा ईरान का भया दोहन, ट्रंप ईरान में वेनेजुएला की तरह नियंत्रण चाहते हैं

अमेरिका और ईरान के बीच गत कुछ महीनों में तनाव एक नए शिखर पर पहुंच गया है। जिसमें न केवल कूटनीतिक, वाणिज्यिक दबाव बल्कि विस्तृत सैन्य तैयारियों और खुले रूप से घुटका की धमकियाँ भी शामिल हैं। पिछले कई महीनों की घटनाओं से यह स्पष्ट नजरिया सामने आयाहै कि यह केवल रीजनल तनाव नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीति का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है। अमेरिका अभी भी आर्थिक,सामरिक एवं राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली राष्ट्र है और आर्थिक रूप से अमेरिका ने ईरान पर बड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसमें तेल निर्यात और वित्तीय लेन-देन को रोकने के साथ-साथ ईरान के सहयोगी देशों और संस्थाओं पर भी अतिरिक्त टैक्स तथा दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। जिससे एजेंसी डेटा बताते हैं कि ईरान की निर्यात-आय सीमित हो रही है, जिससे व्यापक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह प्रतिबंध और दबाव ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम और क्षेत्रीय समर्थित आतंकवाद को रोकने के उद्देश्य से हैं, लेकिन ईरानी नेतृत्व इसे अपने संप्रभुत अधिकारों पर आक्रमण मानता है।

सैन्य दृष्टि से, अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और तैनात नौसैन्य बलों को बड़ा आकार दे दिया है ट्रंप ने बयान दिया है कि यह बेड़ा उस से भी बड़ा है जो उसने वेनेजुएला पर उसकी कार्रवाई से पहले तैनात किया था, और यह बल अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोतों के साथ समुद्री और वायु समूहों को शामिल करता है। अमेरिका का यह बल 'निर्दिष्ट मिशन के लिये तैयार, इच्छुक और सक्षम' बताया जा रहा है और ट्रंप इसे ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिये दबाव का हिस्सा मानते हैं, यह कहते हुए कि हम उम्मीद करते हैं कि

बस केंद्र का कंधा मिल जाए

फैसलों की केंद्रीय गुलामी का दस्तूर यह कि हिमाचल का अपना बजट साहसिक नहीं हो पाता। एक और केंद्र सरकार का बजट हमारे मोहल्ले को बना रहा है कि जागते रहे। कुछ ऐसे दौर हिमाचल की वर्तमान सत्ता के तीन सालों से गुजरे कि राजस्व घाटे की ग्रांट दस हजार से घट कर 3200 करोड़ पहुंच गई और गारंटियां निभाती राज्य सरकार के वित्तीय हाथ ओपीएस निभाते-निभाते छिल गए। जौएसटी का मायावी चेहरा भी रहत का पैगाम लूट कर ले गया। ऐसे में फिर वही घड़ी आई गई जो हर साल को बजट की पैरवी से बांध देती है। केंद्रीय बजट के हवाले से पर्वतीय परिवेश की अमानत का मसौदा पुन-फरियाद कर रहा है। केंद्रीय योजनाओं में पहले ही मनरेगा के पंख टूट चुके हैं, जबकि बाकी संदर्भों की आढ़त में राजनीतिक समीकरण गुंथे गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री की हालिया दिल्ली यात्रा कई मंत्रालयों की कुंडी खड्का चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में सजे हिमाचल के सांसदों से सजग पैरवी की उम्मीद की जा सकती है। हिमाचल के ख्वाबों में रंग भरती फोरलेन परियोजनाओं, रेलवे विस्तार की पटरियों और कांगड़ा एयरपोर्ट की वास्तविकता को अगर केंद्र का सहारा मिले, तो यह पहाड़ी राज्य आत्मनिर्भरता के ढांचे में और पसीना बहा सकता है। कनेक्टिविटी के आधार पर अगर एक पैकेज मिल जाए, तो उनना रक के समानांतर कांगड़ा घाटी रेल या अंब-अंदौरा से निकल कर ट्रेन ज्वालाजी-कांगड़ा पहुंच सकता है। आत्मनिर्भरता में चिन्हित हिमाचल के प्रयासों को केंद्र का सहारा मिल जाए, तो हिमालय से निकलता पानी, भविष्य में आर्थिकी का समुद्र बन सकता है। अभी वाटर सैस के मुहाने पर केंद्र की अड़चनें हिमाचल को जीने देनी दे रही हैं। केंद्र सरकार के उपक्रम हिमाचल से बिजली की पैदावार बढ़ा कर प्रदेश का आर्थिक संबल चुरा रहे हैं। कुछ इसी तरह शानन परियोजना का अवैध संचालन पंजाब में हमारा कह छुपा रह है।

राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत रखा गया, जो पूर्व निर्धारित समीकरण गुंथे गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री की हालिया दिल्ली यात्रा कई मंत्रालयों की कुंडी खड्का चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में सजे हिमाचल के सांसदों से सजग पैरवी की उम्मीद की जा सकती है। हिमाचल के ख्वाबों में रंग भरती फोरलेन परियोजनाओं, रेलवे विस्तार की पटरियों और कांगड़ा एयरपोर्ट की वास्तविकता को अगर केंद्र का सहारा मिले, तो यह पहाड़ी राज्य आत्मनिर्भरता के ढांचे में और पसीना बहा सकता है। कनेक्टिविटी के आधार पर अगर एक पैकेज मिल जाए, तो उनना रक के समानांतर कांगड़ा घाटी रेल या अंब-अंदौरा से निकल कर ट्रेन ज्वालाजी-कांगड़ा पहुंच सकता है। आत्मनिर्भरता में चिन्हित हिमाचल के प्रयासों को केंद्र का सहारा मिल जाए, तो हिमालय से निकलता पानी, भविष्य में आर्थिकी का समुद्र बन सकता है। अभी वाटर सैस के मुहाने पर केंद्र की अड़चनें हिमाचल को जीने देनी दे रही हैं। केंद्र सरकार के उपक्रम हिमाचल से बिजली की पैदावार बढ़ा कर प्रदेश का आर्थिक संबल चुरा रहे हैं। कुछ इसी तरह शानन परियोजना का अवैध संचालन पंजाब में हमारा कह छुपा रह है।

केंद्र हमेशा डबल इंजन सरकार बनकर सोचेगा, तो हमारे हिस्से की आपदा हमों को नोच डलेगी। अभी यूरोपीय यूनियन से हुए व्यापार समझौते के बाद, सेब पर घट रहा आयात शुल्क हिमाचल के बागबानी को चोट ही करेगा। पचास फीसदी आयात शुल्क से घट कर सेब आयात पर अगर अब बीस फीसदी दर से ही अदायगी होती है, तो बाजार की रौनक हिमाचली सेब को रौंद देगी। हैं ज्यादाियां बहुत मगर, सियासत के लिए यह भी एक खेल है। बेशक आशाएं निकलतीं। इस बार भी भारत निर्माण के हर सुनहरे लम्हे से हिमाचल अपनी सदियों गुजारने का विश्वास रखेगा, मगर पर्वत की पीड़ा को बस पीड़ा का ही अंजाम मिलता है। मसलन हिमाचल में अगर रोपवे परियोजनाओं, पर्यटन विकास योजनाओं तथा जल, जंगल और जमीन के सही-सही इस्तेमाल को केंद्र का कंधा मिल जाए, तो यह राज्य स्वतंत्र फैसलों से अपना भविष्य लिख सकता है।

—घनंजय राजौरा

अमेरिका द्वारा ईरान का भया दोहन, ट्रंप ईरान में वेनेजुएला की तरह नियंत्रण चाहते हैं

अमेरिका और ईरान के बीच गत कुछ महीनों में तनाव एक नए शिखर पर पहुंच गया है। जिसमें न केवल कूटनीतिक, वाणिज्यिक दबाव बल्कि विस्तृत सैन्य तैयारियों और खुले रूप से घुटका की धमकियाँ भी शामिल हैं। पिछले कई महीनों की घटनाओं से यह स्पष्ट नजरिया सामने आयाहै कि यह केवल रीजनल तनाव नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीति का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है। अमेरिका अभी भी आर्थिक,सामरिक एवं राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली राष्ट्र है और आर्थिक रूप से अमेरिका ने ईरान नेतृत्व इसे अपने संप्रभुत अधिकारों पर आक्रमण मानता है।

सैन्य दृष्टि से, अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और तैनात नौसैन्य बलों को बड़ा आकार दे दिया है ट्रंप ने बयान दिया है कि यह बेड़ा उस से भी बड़ा है जो उसने वेनेजुएला पर उसकी कार्रवाई से पहले तैनात किया था, और यह बल अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोतों के साथ समुद्री और वायु समूहों को शामिल करता है। अमेरिका का यह बल 'निर्दिष्ट मिशन के लिये तैयार, इच्छुक और सक्षम' बताया जा रहा है और ट्रंप इसे ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिये दबाव का हिस्सा मानते हैं, यह कहते हुए कि हम उम्मीद करते हैं कि

हालांकि कुछ विश्लेषक और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी यह मानते हैं कि सैन्य हमले की संभावना एक बार तय जैसे दृष्टिकोण में पहुंच चुकी है और यह समय की बात है कि हमला कब होगा, न कि क्या होगा, जिससे युद्ध की तैयारी का माहौल और गहरता जा रहा है। इसी बीच ईरान के भीतर भी व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें आई हैं और यह स्थिति आंतरिक असंतोष तथा अमेरिका-के खिलाफ रुख को एक साथ बढ़ा रही कूटनीतिक रूप से, ताजा सूचनाओं के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वे अमेरिका के साथ एक 'न्यायसंत' बातचीत के लिये तैयार हैं, बशर्ते वह धमकियों के साथे में न हो।

शीघ्र सुरक्षा अधिकारियों ने संकेत दिया है कि बातचीत के आयोजन के लिये प्रगति हो रही है। यह दर्शाता है कि खुले युद्ध के साथ-साथ कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं। अरब देश, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय

संतुलन की पतली रस्सी पर बजट 2026

आज 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकार आर्थिक अनुशासन और जनता की आकांक्षाओं के बीच पतली रस्सी पर संतुलन साध रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत स्थिरता, निरंतरता और दीर्घकालिक विकास की सोच से की। कोई अप्रत्याशित और गारंटियां निभाती राज्य सरकार के वित्तीय हाथ ओपीएस निभाते-निभाते छिल गए। जौएसटी का मायावी चेहरा भी रहत का पैगाम लूट कर ले गया। ऐसे में फिर वही घड़ी आई गई जो हर साल को बजट की पैरवी से बांध देती है। केंद्रीय बजट के हवाले से पर्वतीय परिवेश की अमानत का मसौदा पुन-फरियाद कर रहा है। केंद्रीय योजनाओं में पहले ही मनरेगा के पंख टूट चुके हैं, जबकि बाकी संदर्भों की आढ़त में राजनीतिक समीकरण गुंथे गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री की हालिया दिल्ली यात्रा कई मंत्रालयों की कुंडी खड्का चुकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में सजे हिमाचल के सांसदों से सजग पैरवी की उम्मीद की जा सकती है। हिमाचल के ख्वाबों में रंग भरती फोरलेन परियोजनाओं, रेलवे विस्तार की पटरियों और कांगड़ा एयरपोर्ट की वास्तविकता को अगर केंद्र का सहारा मिले, तो यह पहाड़ी राज्य आत्मनिर्भरता के ढांचे में और पसीना बहा सकता है। कनेक्टिविटी के आधार पर अगर एक पैकेज मिल जाए, तो उनना रक के समानांतर कांगड़ा घाटी रेल या अंब-अंदौरा से निकल कर ट्रेन ज्वालाजी-कांगड़ा पहुंच सकता है। आत्मनिर्भरता में चिन्हित हिमाचल के प्रयासों को केंद्र का सहारा मिल जाए, तो हिमालय से निकलता पानी, भविष्य में आर्थिकी का समुद्र बन सकता है। अभी वाटर सैस के मुहाने पर केंद्र की अड़चनें हिमाचल को जीने देनी दे रही हैं। केंद्र सरकार के उपक्रम हिमाचल से बिजली की पैदावार बढ़ा कर प्रदेश का आर्थिक संबल चुरा रहे हैं। कुछ इसी तरह शानन परियोजना का अवैध संचालन पंजाब में हमारा कह छुपा रह है।

सवाल यह है कि बया ये विशाल निवेश ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन करेगा, या केवल महानगरों की चकाचौंध तक सीमित रहेंगे? मध्यम वर्ग, जो देश की जीडीपी में लगभग 40 प्रतिशत योगदान देता है, को इस बजट में टोस कर रहत मिली है। पुरानी कर व्यवस्था में मानक कटौती को 50,000 रुपये से दोगुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया, जबकि वरिष्ठ नगरिकों के लिए यवा और अधिक उदार है। नई कर व्यवस्था में स्लैबों को सरल बनाया गया—5 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर का प्रावधान। शिक्षा ऋण पर टीसीएस हटाय़ा गया (10 लाख रुपये तक), जबकि किराया टीवीएस सीमा को 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया गया। दो स्व-व्यवहृत आवस्यी संपत्तियों पर कर रहत का प्रावधान किया गया है और आयकर रिटर्न दखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया।

कर संहिता को 819 धाराओं से घटाकर 536 धाराओं में सरलीकृत करने का वादा सराहनीय है। ये कदम करदाता को राजस्व का मात्र स्रोत न मानकर भरोसेमंद भागीदार बनाने की दिशा में हैं। हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां मध्यम वर्ग कृषि और सेवा क्षेत्र पर निर्भर है, ये राहते उपभोग बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देंगे।

हालांकि, जमीनी स्तर पर अनुपालन प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा, वरना ये राहते कागजी औपचारिकताओं तक सीमित रह सकती हैं। मध्यम वर्ग की बचत को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने से बाजार में तरलता बढ़ेगी, जो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट को लाभ पहुंचाएगी।

कृषि क्षेत्र, जो अभी भी 18 प्रतिशत जीडीपी और 65 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का आधार है, पर बजट ने विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना को 100 जिलों में विस्तारित किया गया, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया गया, तथा सिंचाई और भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई। मत्स्य पालन

अमेरिका से भारत तक: कीमती धातुओं की हलचल

कमजोरी दिखाई। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय से चली आ रही तेज तेजी ने बाजार को अनोखरबटि स्थिति में पहुंचा दिया था। जब कीमतें वास्तविक मांग और आपूर्ति से कार्पां ओग निकल जाती हैं, तब संतुलन बहाल होना तय होता है। इस बार यह संतुलन तेजी से ओर बड़े पैमाने पर आया।

इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की नीतियों को सबसे प्रभावशाली कारक माना जा रहा है। वहां की मौद्रिक नीति से जुड़े संकेतों ने डॉलर को नई मजबूती दी, जिसने वैश्विक बाजारों की दिशा बदल दी। डॉलर जैसे ही मजबूत होता है, वैसे ही सोना और चांदी जैसी डॉलर आधारित संपत्तियों पर दबाव बढ़ने लगता है। विदेशी निवेशकों ने जोखिम घटाने के लिए सुरक्षित निवेश से दूरी बनानी शुरू कर दी और पूंजी का रुख दूसरी परिसंपत्तियों की ओर मोड़ दिया। अमेरिका के फैसले केवल उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनकी गुंज सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुनाई देती है और भारत जैसे देशों तक असर पहुंचाती है।

वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने निवेशकों को प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से बदल दिया है। अब बाजार युद्ध और टकराव की आशंकाओं से ज्यादा ब्याज दरों की दिशा, डॉलर की मजबूती और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद में आई सुस्ती ने भी मांग की धार को कमजोर किया है। चीन और भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देशों में भौतिक मांग अब भी मौजूद है, लेकिन लगातार ऊंचे भावों के बाद वहां भी सतर्कता का भाव बढ़ा है। वैश्विक कर्ज का बढ़ता बोझ और आर्थिक असंतुलन भले ही दीर्घकाल में सोने के पक्ष में खड़े हों, पर अल्पकाल में डॉलर की ताकत ने

अमेरिका से भारत तक: कीमती धातुओं की हलचल

की कगार पर ले जाकर समझौता करने की ईरान अकेला नहीं है, और एक सीधा युद्ध बहुत खतरनाक और व्यापक बन सकता है।

वेनेजुएला की तुलना में ईरान अन्तरराष्ट्रीय महत्व और रणनीतिक स्थितियों की वजह से कहीं बड़ा मामला है। वेनेजुएला में अमेरिका ने मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में राजनीतिक नियंत्रण और ऊर्जा संधनों पर प्रभाव के लिये कदम उठाये, जबकि ईरान मध्य पूर्व में तेल मार्ग, न्यूक्लियर कार्यक्रम तथा सामरिक प्रभाव के केन्द्र में है। अगर ट्रंप ईरान को वेनेजुएला की तरह कब्जे या शासन परिवर्तन के लिये ले जाने की कोशिश करे, तो यह केवल एक राष्ट्र का सैनिक अधिपत्य नहीं बल्कि एक वैश्विक प्रतिद्वंद्वी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास होगा, जिसका परिणाम क्षेत्रीय युद्ध, तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल, और विश्व राजनीति में और गहरी विभाजन की स्थिति हो सकता है। इस समय ताज़ा हालात यह संकेत देते हैं कि अमेरिका पूरी सैन्य तैयारी के साथ खड़ा है, ईरान भी कठोर प्रतिक्रिया के लिये तैयार है, और कूटनीतिक प्रयास संघर्ष को नियंत्रण में रखने के लिये जारी हैं। लेकिन खुला युद्ध अभी टल नहीं पाया है और दोनों पक्षों की कठिन स्थिति वैश्विक राजनीति के लिये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ट्रंप ईरान को वेनेजुएला की तरह अपने अधिपत्य में ले सकरता है? वर्तमान संकेत यह दिखाते हैं कि सैन्य नियंत्रण के बजाय अमेरिका अधिकतर दबाव और बातचीत के द्वारा ही परिणाम चाहता है, पर यह भी स्पष्ट है कि अगर ईरान बातचीत में मुश्क शर्तें नहीं मानता तो सैन्य विकल्पों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है और यह सम्भावना वैश्विक राजनीति के लिये गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

—संजीव ठाकुर

अमेरिका से भारत तक: कीमती धातुओं की हलचल

अमेरिका और ईरान के बीच गत कुछ महीनों में तनाव एक नए शिखर पर पहुंच गया है। जिसमें न केवल कूटनीतिक, वाणिज्यिक दबाव बल्कि विस्तृत सैन्य तैयारियों और खुले रूप से घुटका की धमकियाँ भी शामिल हैं। पिछले कई महीनों की घटनाओं से यह स्पष्ट नजरिया सामने आयाहै कि यह केवल रीजनल तनाव नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीति का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है। अमेरिका अभी भी आर्थिक,सामरिक एवं राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली राष्ट्र है और आर्थिक रूप से अमेरिका ने ईरान नेतृत्व इसे अपने संप्रभुत अधिकारों पर आक्रमण मानता है।

सैन्य दृष्टि से, अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और तैनात नौसैन्य बलों को बड़ा आकार दे दिया है ट्रंप ने बयान दिया है कि यह बेड़ा उस से भी बड़ा है जो उसने वेनेजुएला पर उसकी कार्रवाई से पहले तैनात किया था, और यह बल अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोतों के साथ समुद्री और वायु समूहों को शामिल करता है। अमेरिका का यह बल 'निर्दिष्ट मिशन के लिये तैयार, इच्छुक और सक्षम' बताया जा रहा है और ट्रंप इसे ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिये दबाव का हिस्सा मानते हैं, यह कहते हुए कि हम उम्मीद करते हैं कि

हालांकि कुछ विश्लेषक और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी यह मानते हैं कि सैन्य हमले की संभावना एक बार तय जैसे दृष्टिकोण में पहुंच चुकी है और यह समय की बात है कि हमला कब होगा, न कि क्या होगा, जिससे युद्ध की तैयारी का माहौल और गहरता जा रहा है। इसी बीच ईरान के भीतर भी व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें आई हैं और यह स्थिति आंतरिक असंतोष तथा अमेरिका-के खिलाफ रुख को एक साथ बढ़ा रही कूटनीतिक रूप से, ताजा सूचनाओं के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वे अमेरिका के साथ एक 'न्यायसंत' बातचीत के लिये तैयार हैं, बशर्ते वह धमकियों के साथे में न हो।

शीघ्र सुरक्षा अधिकारियों ने संकेत दिया है कि बातचीत के आयोजन के लिये प्रगति हो रही है। यह दर्शाता है कि खुले युद्ध के साथ-साथ कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं। अरब देश, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय

विकास के लिए अंडमान-लक्षद्वीप में आर्थिक क्षेत्र घोषित किए गए, फल-सब्जी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का प्रावधान। मनरेगा बजट में वृद्धि, ग्रामीण क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण सुगम बनाया गया। चमड़ा-फुटवियर और विलाेना उद्योगों से 22 लाख नए रोजगार का अनुमान है। हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य में, जहां गेहूं-धान चक्र प्रमुख है, फसल विविधीकरण से मिट्टी स्वास्थ्य सुधरेगा और आय अस्थिरता कम होगी। ये प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देंगे, लेकिन वास्तविक परीक्षा यही होगी कि क्या ये योजनाएं कागजों से निकलकर खेतों, बाजारों तक पहुंच पाएंगी। छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलना चाहिए, न कि बड़े जमींदारों तक सीमित रहना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से किसानों को सीधे उपभोक्ता से जोड़ना ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा।

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए लक्ष्मी वंदना योजना का विस्तार किया गया, स्वरोजगार ऋण पर गारंटी हटाई गई (20 लाख तक)। शहरी महिलाओं के लिए घर-आधारित कार्य को कर छूट का लाभ दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां महिला आरक्षण 50 प्रतिशत है, वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए एसएचजी ऋण और कौशल प्रशिक्षण से आर्थिक स्वावलंबन बढ़ेगा। पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व से स्थानीय मुद्दे जैसे जल संधि, स्वच्छता बेहतर होंगे। लेकिन पंचायत स्तर तक प्रायवी क्रियान्वयन जरूरी होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी बाधाएं हैं। हरियाणा में 50त आरक्षण का लाभ उठाकर महिलाएं पंचायतों को परिवर्तन का माध्यम बना सकती हैं।

देश की 60 प्रतिशत युवा आबादी (35 वर्ष से कम) को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान। इसमें 50 नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्कूल

कनेक्टिविटी का प्रारंभिकता देते हुए लक्ष्मी वंदना योजना का विस्तार किया गया, स्वरोजगार ऋण पर गारंटी हटाई गई (20 लाख तक)। शहरी महिलाओं के लिए घर-आधारित कार्य को कर छूट का लाभ दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां महिला आरक्षण 50 प्रतिशत है, वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए एसएचजी ऋण और कौशल प्रशिक्षण से आर्थिक स्वावलंबन बढ़ेगा। पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व से स्थानीय मुद्दे जैसे जल संधि, स्वच्छता बेहतर होंगे। लेकिन पंचायत स्तर तक प्रायवी क्रियान्वयन जरूरी होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी बाधाएं हैं। हरियाणा में 50त आरक्षण का लाभ उठाकर महिलाएं पंचायतों को परिवर्तन का माध्यम बना सकती हैं।

देश की 60 प्रतिशत युवा आबादी (35 वर्ष से कम) को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान। इसमें 50 नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्कूल

कनेक्टिविटी का प्रारंभिकता देते हुए लक्ष्मी वंदना योजना का विस्तार किया गया, स्वरोजगार ऋण पर गारंटी हटाई गई (20 लाख तक)। शहरी महिलाओं के लिए घर-आधारित कार्य को कर छूट का लाभ दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां महिला आरक्षण 50 प्रतिशत है, वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये कदम लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए एसएचजी ऋण और कौशल प्रशिक्षण से आर्थिक स्वावलंबन बढ़ेगा। पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व से स्थानीय मुद्दे जैसे जल संधि, स्वच्छता बेहतर होंगे। लेकिन पंचायत स्तर तक प्रायवी क्रियान्वयन जरूरी होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी बाधाएं हैं। हरियाणा में 50त आरक्षण का लाभ उठाकर महिलाएं पंचायतों को परिवर्तन का माध्यम बना सकती हैं।

देश की 60 प्रतिशत युवा आबादी (35 वर्ष से कम) को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान। इसमें 50 नए आईआईटी और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्कूल

कनेक्टिविटी का प्रारंभिकता देते हुए लक्ष्मी वंदना योजना का विस्तार किया गया, स्वरोजगार ऋण पर गारंटी हटाई गई (20 लाख तक)। शहरी महिलाओं के लिए घर-आधारित कार्य को कर छूट का लाभ दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान हरियाणा जैसे राज्यों में, जहां महिला आरक्षण 50 प्रतिशत है, वास्तविक नेत

साइबर ठगी मामले में 9 गिरफ्तार, 2 लाख रुपए जब्त

गिरोंह के पास 19 मोबाइल और फर्जी दस्तावेज मिले, 13 लाख फ्रीज

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ऑपरेशन मैट्रिक्स के तहत पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोंह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 लाख रुपये नकद, 19 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज, एटीएम कार्ड और एक लम्बरी कार जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त, साइबर धोखाधड़ी से जुड़े लगभग 13 लाख रुपये बैंक खातों में फ्रीज कराए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी युवाओं को लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे। इन खातों के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश का झंसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी की जाती थी। ठगी की गई रकम को असली अपराधियों की पहचान छिपाने के लिए म्यूचुअल बैंक खातों के जरिए इधर-उधर ट्रांसफर किया जाता था। पुलिस को सूचना



मिली थी कि शहर के एक होटल में कुछ संदिग्ध युवक एक टाटा नेक्सॉन कार जब्त की है।

उठे हुए हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और साइबर ठगी से जुड़े आरोपियों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 मोबाइल फोन, 2 चेकबुक, एटीएम कार्ड, आधार-पैन कार्ड, वाई-फाई डिवाइस, सीसीटीवी कैमरे और

संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 29 लाख 77 हजार रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोंह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और आने वाले समय में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुनेश्वर सेन (निवासी धर्मपुरा, दमोह), पीयूष पिता अनिल बिहारे (थाना एरोडम, इंदौर), शुभम जोशी (न्यू विज्ञान नगर, डाइट रोड, टोंक, राजस्थान), आशीष उर्फ गोलू जैन (पुराना थाना, दमोह), गौरव जैन (जैन मंदिर के पास, मेन रोड, धनोरा, सिवनी जिल्ला), मंजोत भाटी (म.नं. 110-ए, नगीन नगर, थाना एरोडम, इंदौर), नितेश बिरला (गोवर्धन पैलेस, शिरपुर धार रोड, इंदौर, हाल मुकाम नंदवाग रोड, इंदौर), जितेंद्र उर्फ जीतू राजपूत (13 न्यू गांधी पैलेस, इंदौर, हाल मुकाम इंदौर) और शुभम उर्फ शुब्बु (राजनगर, इंदौर) शामिल हैं।

अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहर निषाद भोंई समन्वय समिति म.प्र. की कार्यकारिणी घोषित

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहर निषाद भोंई समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक राजाराम कश्यप एवं महासचिव दिलीप कश्यप ने अध्यक्ष मदनलाल कहर की अनुसंधान पर म.प्र. राज्य की कार्यकारिणी घोषित की। जिसमें उपाध्यक्ष ओमप्रकाश रायकवार, पी.सी. रायकवार, भगवान भोंई, महामंत्री राजेन्द्र सौथिया, प्रदेश मंत्री सुनील साहनी, रामस्वरूप रायकवार, भूपेन्द्र वर्मा, कोषाध्यक्ष शरद रायकवार तथा सदस्य एन.पी. बाथम, डॉ. सी.एस. बाथम, जसवंतसिंह माझी, सुनील रायकवार, अम्बालाल चौहान, अनिल रायकवार, दिनेश पडव्यापती, जगदीश बाथम, महेश रायकवार, धर्मेन्द्र कश्यप, ज्ञानी रायकवार, बालकिशन रायकवार, कैलाश रायकवार, सुभाष धुरिया, घनश्याम कहर, रविन्द्र बाथम, सालिकराम धीवर, दिनेश बावने, ओमप्रकाश कड्डा, डॉ. संतोष रायकवार, खेमचंद्र केवट, जितेंद्र वर्मा को नियुक्त किया है। श्री कहर ने बताया कि शीघ्र ही जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। श्री कहर ने आगे बताया कि समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों को जोड़ना व आपसी तालमेल बनाए रखना। शिक्षा को बढ़ावा समाज के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और छात्रवृत्ति की जानकारी उपलब्ध कराना। अधिकारों के प्रति जागरूक करना। आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं (जैसे आरक्षण, सब्सिडी) का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। कौशल विकास युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों से जोड़ना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सरकारी योजनाओं का लाभ मत्स्य पालन, छोटे उद्योगों और स्वरोजगार के लिए मिलने वाले सरकारी लोन दिलाने में समाज के युवाओं को मदद करना। समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाना। एकजुटता समाज के सामूहिक कार्यक्रमों, युवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों और विवाह समारोहों का आयोजन करना ताकि सामाजिक एकता बढ़े। प्रशासनिक संपर्क समाज की स्थानीय समस्याओं को जिला प्रशासन या सरकार तक पहुंचाना और उनका समाधान करवाना। राजनीतिक चेतना समाज की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना है।

खेलों एमपी यूथ गेम्स में दक्ष राणा ने हासिल किया कांस्य पदक

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। 28 से 31 जनवरी तक न्यालिगर में आयोजित राज्य स्तरीय खेल एमपी यूथ गेम्स में देवास के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ी दक्ष राणा ने बालक अंडर-19 सिंगल्स वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। दक्ष की इस उपलब्धि से देवास जिले का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित हुआ है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दक्ष ने भोपाल के खिलाड़ी आर्यन शर्मा को शानदार अंदाज में सीधे सेटों में 21-8, 21-14 से पराजित कर टॉप-4 में मजबूत जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंदौर के खिलाड़ी कन्हैया शर्मा से हुआ, जहाँ संघर्षपूर्ण मुकाबले में दक्ष 15-21, 15-21 से पराजित हुए और उन्हें प्रतियोगिता का कांस्य पदक प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि दक्ष राणा सोनीपत में हरिंदर मलिक से व कुशाभाऊ ठाकरे इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में देवास जिले के एकमात्र साईं डिलोमा एनआईएस कोच अर्जुन सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दक्ष की इस सफलता पर देवास विधायक गायत्री राजे पवार, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव खडेलवाल, नगर निगम सभापति रवि जैन, पूर्व पार्षद दिलीप सिंह ठाकुर, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अशोक लखमानी।

पर्यावरण-अनुकूल तकनीक को बढ़ावा देने वाला और घरेलू मैनुफैक्चरिंग को मजबूत करने वाला बजट- विजयवर्गीय



देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। चाटेंट अकाउंटेन्ट भरत विजयवर्गीय ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि केंद्रीय बजट 2026 को देखा जाए तो यह बजट पर्यावरण-अनुकूल तकनीक को बढ़ावा देने वाला और घरेलू मैनुफैक्चरिंग को मजबूत करने वाला साबित होगा। सरकार स्पष्ट कर स्लैब वाली सरल आयकर प्रणाली की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्थाओं में मौजूदा कर स्लैब और दरों को बनाए रखने का विकल्प चुना है और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा को अपडेट किया गया है। अब 31 मार्च तक कम फीस के साथ संशोधित आईटीआर दाखिल किया जा सकेगा। मोटर एक्सिजेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गयी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक में इंट्र-डे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स मार्केट में पैन्युच पर रोक लगाने के लिये 'ज्ज' में बढ़ोतरी की है ताकि निवेशकों को लंबे समय के लिए बाजार में निवेश करने के लिये प्रेरित किया जा सके क्योंकि 90 प्रतिशत निवेशकों को ट्रेडिंग में नुकसान होता है।

केंद्रीय बजट हुआ पेश, किसी ने बताया हर वर्ग के विकास का बजट, किसी को नजर आई खामियां

केंद्रीय बजट को लेकर सामने आई मिली जुली प्रतिक्रिया

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद पहुंचकर केंद्र का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बजट पेश करते हुए किसान, आमजन को लेकर जो भी कुछ शामिल किया गया था उसे पेश किया गया।

बजट की चर्चा नगर में भी दिनभर चलती रही। किसी ने इस बजट को लेकर आम आदमी की जेब भरने वाला और विकास का बजट बताया तो किसी ने इसकी कमियां गिनाते हुए अपनी बात रखी। जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार भी मर रहा।

इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास- विधायक अरूण भीमावद- लोकसभा में रविवार को पेश किए गए बजट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। जिसमें गरीब कल्याण, युवा, महिलाओं और गरीब कल्याण के लिए जो जरूरी है सभी को शामिल

किया गया है। इस बजट की विशेषता है आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाना। सबका साथ सबका विकास की भवना को लेकर इस बजट में सारी सुविधा देने का प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया गया है।

उप निरीक्षक हिमांशु पांडे की मुस्ती से खुली पोल-दिनांक 29 जनवरी 2026 को एम.जी. रोड मंडी गेट, सोनकच्छ पर सूचना मिली कि कुछ युवक तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिलों में अवैध पटाखा साइलेंसर लगाकर शहर की शांति भंग कर रहे हैं।

हर वर्ग के विकास का बजट-पं. आशीष नागर- देश की वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह देश के विकास को प्रदर्शित करता है। इस बजट की विशेषता यही है कि देश की सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है। हर वर्ग के विकास को शामिल किया गया है। वर्ष 2047 में विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए वर्ष

2026 का बजट है। जिसमें महिलाओं, युवाओं के साथ-साथ स्वर्णिम भारत की तस्वीर नजर आती है।

सपनों को नई उड़ान देने वाला बजट है- देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशानुसार रविवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वह किसानों और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला बजट है। इस बजट में केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के उज्वल भविष्य का रूपांशु प्रिंट है। इस बजट में मजदूरों का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचे इसका ध्यान रखा गया है। साथ ही 2047 का जो विजन है विकसित भारत का उसे ध्यान में रखकर इस बजट को प्रस्तुत किया गया है जो बहुत सुंदर है।

- डॉ. रवि पांडे, जिलाध्यक्ष भाजपा लोक लुभावन बजट है। बजट में न महंगाई कम की गई है और न ही मध्यम वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया

129/194(डी), 190(2), 3/181, 51/177, 130/177(3) मोटर स्कीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चारों बुलेट मोटरसाइकिलें जब्त कर पुलिस कब्जे में ली गई।

पकड़े गए युवक- गगन पिता राजपात सिंह सायल (22), ग्राम कराडिया परी, विनोद विश्वकर्मा पिता जगदीश विश्वकर्मा (18), ग्राम चांदाखेड़ी, अनिराज सिंह संभव पिता मुकेश सिंह संभव (18), ग्राम लसुडिया हाथु, थाना हाटपिपल्या

जब्तशुदा बुलेट वाहन- एम.पी. 07 एन.जे. 7371, एम.पी. 09 बी.क्यू. 4867, एम.पी. 09 जेट.वी. 8382, एम.पी. 41 जेट.एच. 4524

कौन रहे कार्रवाई के हीरो- इस सनसनीखेज कार्रवाई में थाना प्रभारी अजय गुर्जर एवं उपनिरीक्षक हिमांशु पांडे की भूमिका सबसे अहम रही। साथ ही उपनिरीक्षक मान सिंह, प्रअर हरिओम यादव, विकास, आरक्षक सत्येंद्र, श्याम बिहारी, लक्ष्मण, कुलदीप, रवि पाटीदार, अखिलेश, सुनील, रितेश एवं सतीश का सराहनीय योगदान रहा।

- रामवीरसिंह सिकरवार, प्रदेश महासचिव महंगाई को कम करने और लोगों के विकास को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट से व्यापार-व्यवसाय को भी काफी लाभ मिलेगा। कुछ कमियां जरूर हैं जिसे दूर किया जाना था। लेकिन कुल मिलाकर इस बजट को हर वर्ग का ध्यान में रखकर बनाया गया है। महिलाओं के विकास को लेकर जो योजनाएं शामिल की गई हैं उसके लिए केंद्र की सरकार काबिल-ए-तारीफ है।

- अनुराग तिलगोता, कपड़ा व्यवसायी

मृत्यु के बाद भी अमर हुई मानवता- सेवाधाम आश्रम के सेवादार का देहदान, राजकीय सम्मान के साथ दी गई विदाई

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मानवता की सेवा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आज देवास का अमलतास मेडिकल कॉलेज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। सेवाधाम आश्रम (अंकितग्राम) में निवासरत श्रीमती गीता बाई उम्र, 67 का देहदान संकल्प शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्ण हुआ।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार, देहदानियों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए अमलतास मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस विभाग की टुकड़ी द्वारा गाई ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इस भावुक क्षण के दौरान वहां उपस्थित पुलिस बल, कॉलेज डीन डॉ.ए.के. पिचवा,एनार्टोमी विभाग के हेड डॉ. करखायले एम. एल, मेडिकल छात्र, डॉक्टर्स और



परिजनों ने नम आंखों से इस महान आत्मा को अंतिम विदाई दी।

यह पुनीत कार्य सेवाधाम आश्रम, ग्राम अम्बोदिया (उज्जैन) के संस्थापक श्री सुधीर भाई गोयल के विशेष प्रयासों से संपन्न हुआ। गोयल जी ने बताया कि आयुष्य विभाग के निर्देशों और मृतकों

की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए यह देहदान किया गया है। उन्होंने कहा, यह देहदान न केवल चिकित्सा जगत के शोध में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि भविष्य के डॉक्टरों को मानव शरीर की जटिलताओं को समझने में भी मदद करेगा।

देहदान अधिकारी, श्री गजानंद चौहान, ने देहदान की प्रक्रिया की जानकारी दी और इसे संपन्न कराया।

अमलतास वेलफेयर सोसायटी के चेयरमैन महोदय ने श्री सुधीर भाई गोयल जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज को ऐसे महान कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी देह दान करता है, तो वह समाज को जीवन देने वाले नए डॉक्टरों के निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान देता है।

सोनकच्छ में बुलेट आतंक पर पुलिस का प्रहार

थाना प्रभारी अजय गुर्जर का सख्त एक्शन



सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय गुर्जर के निर्देश पर-उपनिरीक्षक हिमांशु पांडे ने तत्काल वाहन चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान 04 बुलेट मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं, जिनमें अवैध मांडिकाइड साइलेंसर लगे पाए गए। वाहन चालक आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सके। कानून का करारा तमाचा- चारों वाहन चालकों के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 02 से 05/31.01.26, धारा

अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही कर 5 प्रकरण दर्ज किए



देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर ऋगुज सिंह के निर्देशानुसार जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा आबकारी वृत्त सोनकच्छ और कन्नौद में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की। विभाग द्वारा दिनांक 31/01/2026 को आबकारी टीम द्वारा वृत्त कन्नौद में नीमखेड़ा रोड, ग्राम कोठड़ा में मोटर साइकिल स्लेंडर प्लस से 02 पेट्री देशी मदिरा का अवैध रूप से परिवहन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 75000 हजार रूपए आंका गया है। दिनांक 31/01/2026 को वृत्त सोनकच्छ में ग्राम जलोदिया, पोलाई, बड़ी चुरलाई, बाबाई, जलेरिया, खेरिया साहू, गंजपुरा और बस स्टैंड सोनकच्छ में आबकारी टीम द्वारा दबिश गश्त कार्य किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत 05 प्रकरण दर्ज किए गये। 35 पाव देशी मदिरा, 40 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य 11,000 रुपये आंका गया। कार्रवाई में नीलेश पवार सहायक जिला आबकारी अधिकारी, प्रेम यादव आबकारी उप निरीक्षक, राजाराम रैक्वार मुख्य आबकारी आरक्षक, बालकृष्ण जायसवाल, अरविंद जिनवाल,निहाल खत्री, विकास गौतम, भगवत परते आबकारी आरक्षक, अनिल अकोदिया, अनिल चौहान नगर सैनिक उपस्थित रहे। इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह अपनी सामाजिक समस्या यात्रा के तहत शाजापुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी फिलहाल मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताते हुए लोगों के बीच पहुंचने की बात कही। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि उनकी यह यात्रा गुना, अशोकनगर और राजगढ़ जिले की सभी विधानसभाओं को कवर करने के बाद शाजापुर जिले में पहुंची है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। इसके माध्यम से वे बिना किसी तामझाम के हाट-बाजारों, गांवों और छोटे समूहों के बीच जाकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश और प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। पार्टियों में गुटबाजी से जुड़े सवाल पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ऊपर से चलती हैं, जिसके कारण गुटबाजी बनी रहती है। इंदौर में दूषित पानी की घटना पर उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही और नेताओं के अहंकार को जिम्मेदार ठहराया।

जिला स्तरीय कर्मचारी

सम्मेलन सोनकच्छ में संपन्न



देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्य प्रदेश नगर निगमदुनगर पालिका कर्मचारी संघ के तत्वावधान में सोनकच्छ में आयोजित जिला स्तरीय कर्मचारी सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में जिले की समस्त नगरीय निकाय इकाइयों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सम्मेलन में नगर परिषद सोनकच्छ अध्यक्ष प्रतिनिधि कृष्ण पाल सिंह बखेल विशेष अतिथि के रूप में एवं प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि श्री सोलंकी द्वारा नगरीय निकायों की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं तथा आगामी कार्य योजना पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने विभाग से जुड़े ज्वलंत मुद्दों, विशेषकर वेतन भुगतान में हो रही देरी, वित्तीय अव्यवस्थाओं एवं कर्मचारियों के अधिकारों पर गंभीर चर्चा की। सम्मेलन में यह तथ्य प्रमुखता से सामने आया कि कई नगरीय निकायों में कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन का आहरण नहीं हो पाया है, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी एवं आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। साथ ही वर्ष 2016 तक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर जोर दिया गया इस अवसर पर प्रदेश सचिव हरेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा कर्मचारियों को प्रदेशव्यापी आंदोलन की विस्तृत कार्य योजना से अवगत कराया गया।

देश की सुरक्षा करेगा सहज पब्लिक स्कूल का प्रद्युम्न पटेल

शिक्षकों के मार्गदर्शन से मिला मेहनत को मुकाम, इंडियन एयर फोर्स में हुआ चयन



शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। दुपाड़ा रोड स्थित सहज पब्लिक स्कूल के एक और छात्र ने विद्यालय और नगर का नाम रोशन किया है, जिसने अपनी मेहनत और शिक्षक-शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन से अपने सपनों को साकार करने में सफलता हासिल की है। प्रद्युम्न पटेल का चयन एयरफोर्स के लिए हुआ है। जिसकी इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त करते हुए उसके उज्वल भविष्य की

कामना की है। प्रद्युम्न का बचपन से ही देश की सेवा करने का सपना था। अपनी यह मंशा प्रद्युम्न ने अपने प्राचार्य डॉ. अंकुर जैन को बताई, जिन्होंने उसे सहज पटेल दिवा और इसके लिए की जाने वाली तैयारियों व परीक्षा के बारे में बताया। यही नहीं उन्होंने विद्यालय की

शिक्षक-शिक्षिकाओं के माध्यम से भी प्रद्युम्न को सही राह दिखाई। इसके बाद बारी थी कड़ी मेहनत की जिससे प्रद्युम्न ने कभी मुंह नहीं मोड़ा। नतीजा यह हुआ कि प्रद्युम्न का चयन इंडियन एयरफोर्स में कारपोरल पद पर हुआ है, जिसे दिल्ली में अपने देश की सेवा करने का मौका मिला। इस सफलता पर विद्यालय प्राचार्य डॉ. अंकुर जैन ने कहा कि प्रद्युम्न की यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है और यह सिद्ध करती है कि निरंतर मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। संचालिका आशा जैन सहित विद्यालय परिवार ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए प्रद्युम्न के उज्वल भविष्य की कामना की है।

सनातन प्रीमियर का हुआ समापन, विजेता बनी आईएमए हितांशु इलेवन, उप विजेता बनी श्री सांवरा इलेवन



शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। मित्र सेवा समिति के तत्वावधान में विकास सिंदल द्वारा आयोजित प्रथम सनातन प्रीमियर लीग का समापन रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ। जिसमें विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और 1 रन से हार-जीत का फैसला हुआ। फायनल मुकाबला अंतिम गेंद तक जारी रहा और आईएमए हितांशु इलेवन ने श्री सांवरा इलेवन को 1 रन से हराकर ट्राफी उठाई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अरूण भीमावद थे तथा विशेष अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष पं. आशीष नागर, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, शुजालपुर मुंडल

अध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी, महामंत्री योगेंद्र शिवदरे, शाजापुर मंडल महामंत्री गोविंद नायक, रामजी बडिया, राजेश पाटीदार, विकास पाटीदार, निहाल दलोदिया, यश माथुर आदि उपस्थित थे। इसके बाद विधायक श्री भीमावद ने विजेता टीम को ट्राफी व 31 हजार रू. एवं उप विजेता टीम को ट्राफी व 15 हजार का नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री चौहान ने मैच ऑफ द मैच का पुरस्कार विवेक नुवे पोलाई को तथा मैच ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दुमने मीणा को प्रदान किया।

बलवंती नदी शुद्धिकरण व कार्याकल्प का काम शुरू

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सालों से उपेक्षा का शिकार हो रही बलवंती नदी के दिन अब फिरने वाले हैं। नदी के शुद्धिकरण के लिए काम शुरू हो चुका है। 13 करोड़ 11 लाख की लागत से नदी का पुराना वैभव पुनः लौटगा।

नगरीय क्षेत्र में करीब 6 किलोमीटर क्षेत्र में होकर गुजर रही नदी के सौंदर्यकरण के साथ शुद्धिकरण के लिए रिविवा से काम शुरू हो चुका है। बस स्टैंड क्षेत्र में पोखलेन मशीन से नदी का चौड़ीकरण व समतलीकरण करने के साथ बड़े पाईप



डालना शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 3.30

करोड़ रुपए की लागत से पेटलावद रोड स्थित नागेश्वर धाम के पास बलराम धाम में सुविधायुक्त उद्यान बनेगा। दूसरे चरण में 13.11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें नदी के दोनों किनारों पर आरसीसी पाइप 7 सी एवं 1 हजार एमएम के डाले जाएंगे। जिससे दोनों ओर से नदी में मिल रहे दूषित जल ट्रीटमेंट प्लांट तक जा सकेगा। नदी क्षेत्र के कुल 6.4 किलोमीटर में नदी के दोनों ओर पाइप डालेंगे। इसी के साथ 225 चैबर

दोनों साइड बनेंगे। पाइप द्वारा नदी के दूषित जल के उपचार हेतु कुल 3 एमएलडी की क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित होगा। जिसमें उपचारित स्वच्छ जल को नदी में रोकने हेतु एक 15 फीट उंचे स्टॉप डैम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा नदी में जहां किनारे क्षतिग्रस्त हुए वहां आरसीसी रिटेंनिंग वाल का निर्माण भी किया जाएगा। कार्य की शुरुआत के अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शेखर यादव, उपाध्यक्ष राजेंद्रसिंह पंवार, पाण्डे सुखराम देवदा, संतोष चौहान, दीपक जाधव, संतोष राव, उपयंत्री सारंग पौराणिक आदि मौजूद थे।

विकासखंड परासिया में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जयंती

छिन्दवाड़ा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के मुखिया एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के आह्वान पर जिला कलेक्टर श्री हर्षेन्द्र नारायण के निर्देशानुसार जिला समन्वयक श्री अखिलेश जैन व विकासखण्ड समन्वयक श्री संजीव भावकर एवं परामर्शदाता श्री मनीष कैथवास के मार्गदर्शन में आज विकासखंड परासिया में संत श्री शिरोमणि रविदास जी की जयंती



मनाई गई। जिसमें सर्वप्रथम संत शिरोमणि रविदास जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर सभी समितियों द्वारा पूजा अर्चना किया गया। परामर्शदाता श्री

मनीष कैथवास के द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन चरित्र पर विस्तारपूर्वक उद्घोषण उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों के समक्ष दिया गया। उन्होंने मनचंगा, तो कटौती में गंगा के शिरोमणि रविदास जी के वाक्य को समझाते हुए सभी को समझता का भाव आरसी मेलजोल बढ़ाने एक दूसरे के सहयोगी बनने के बारे में बताकर संत रविदास जी के जीवन चरित्र का वर्णन किया।

खेती के साथ मशरूम का साथ, बिछिया के किसानों की बढ़ती आय और नई पहचान

मंडला/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कहते हैं, छोटी शुरुआत भी बड़ी कामयाबी की राह खोल देती है बिछिया क्षेत्र के किसानों ने इसे सच कर दिखाया है।पारंपरिक खेती पर निर्भर किसानों की आय सीमित थी, लेकिन अब मशरूम उत्पादन ने उनकी जिंदगी में नई रोशनी भर दी है। प्रशासन की पहल, प्रशिक्षण और किसानों की मेहनत ने इस छोटे से प्रयोग को आर्थिक सशक्तिकरण के मॉडल में बदल दिया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्रीमती सोनाली देव और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री मुकेश कुलस्ते के मार्गदर्शन में विशेष प्रशिक्षण



कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 70 किसानों को मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। आजीविका परियोजना के सहयोग से नरेनी माल, कन्हारी कला, गदिया चंगरिया के लगभग 50 किसान

सफलतापूर्वक मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। इस मुहिम में श्री मनोज धूमकेती और श्रीमती बैसखिया बाई मास्टर ट्रेनर बनकर अन्य किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उनका प्रयास अब एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है।ग्राम नरेनी माल के किसान मनोज धूमकेती ने साबित कर दिया कि कम संसाधनों में भी बड़ी कमाई संभव है। किसान श्री मनोज धूमकेती ने मात्र 10म10 फीट के छोटे कमरे में मशरूम उत्पादन शुरू कर अच्छी कमाई कर ली है। उन्होंने बताया कि 50 मशरूम बेड तैयार करने में केवल 2 हजार रुपये का खर्च आया। उत्पादन के एक चक्र में ही उन्हें लगभग 8 हजार रुपये की आय प्राप्त हुई।

मोहखेड़ के किसान कैलाश पवार ने पथरीली भूमि में जी-9 केले की खेती से रचा नवाचार



संभव है। उन्होंने गत वर्ष अप्रैल माह में पुणे से जी-9 किस के पौधे मंगवाकर ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ रोपण किया था, जो मात्र लगभग 11 माह में पूरी तरह तैयार हो गई है।

किसान श्री पवार के अनुसार 15 फरवरी के बाद मार्च माह तक पूरी फसल की कटाई हो जाएगी और प्रति एकड़ ढाई से तीन लाख रुपये तक लाभ होने की संभावना है। फसल की गुणवत्ता को देखते हुए जबलपुर एवं नागपुर के व्यापारियों ने खेत पर पहुँचकर निरीक्षण किया है तथा वे सीधे खेत से ही उपज खरीदने के लिए संपर्क कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि यह केला पथरीली एवं मुसम वाली उस भूमि पर उगाया गया है, जहाँ सामान्यतः अन्य फसलें लेना संभव नहीं माना जाता।

कृषि विभाग की टीम ने भी खेत पर पहुँचकर इस नवाचार का अवलोकन किया और किसान द्वारा अपनाई गई तकनीकों की सराहना की।

छिन्दवाड़ा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। छिन्दवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम भुताई के प्रगतिशील किसान श्री कैलाश पवार ने नवाचार के माध्यम से कृषि क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। श्री पवार ने लगभग 18 एकड़ क्षेत्र में केले की उन्नत किस्म जी-9 की खेती कर यह साबित कर दिया है कि कठिन मानी जाने वाली भूमि में भी आधुनिक तकनीक के सहारे बेहतर उत्पादन संभव है।

ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने खेल के माध्यम से बहुत ही अच्छा कदम डॉक्टर राघवेंद्र पवार

ग्राम चितावद में विधानसभा स्तरीय ग्रामीण युवा टेनिस क्रिकेट का शुभारंभ



अकोदिया/ अमर सिंह मेवाड़ा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सलसलाई ग्रामीण क्षेत्र में उभरती हुई प्रतिभा को एक अच्छा मुकाम मिले और वहाँ एक अच्छे खिलाड़ी बने यहाँ हम सब सोते हैं और यहाँ आज विधानसभा स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजित हो रही है यहाँ ग्रामीण युवाओं को उभरते हुए खेल के माध्यम से विधानसभा स्तरीय जो क्रिकेट प्रतियोगिता है यहाँ एक उचित कदम है उक्त बातें ग्राम चितावद में विधानसभा स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉ राघवेंद्र अजब सिंह पवार के द्वारा व्यक्त की जहाँ मुख्य अतिथि

आयोजित समिति के संरक्षक चिराग परमार मौजूद थे अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच रमेश कासनिया द्वारा की गई विशेष अतिथि पूर्व सरपंच दिनेश पटेल प्रदीप परमार पत्रकार आनंद मेवाड़ा टीकम राजपूत मनोज परमार शेताब मेवाड़ा युवराज राजपूत जेपी परमार मौजूद जहाँ अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी के चित्र मल्यार्पणकर शुभारंभ किया जहाँ उसके पश्चात पहला मुकाबले नौलाय व किटोर के बीच में हुआ जहाँ अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों को उत्सवधर्न के साथ परिचय किया गया वहीं दूसरा मुकाबला सलसलाई व मुडलाय के बीच में हुआ जहाँ सलसलाई व किटोर टीम विजय हुई वहीं मैन ऑफ द मैच का मौके पर पुरस्कार दिया गया आयोजित समिति के सुभाष कसनिया ने बताया कि प्रतिदिन 50 से अधिक टीम विधानसभा है इसमें सम्मिलित हुई अभी तक जहाँ आज शाम तक कितने टीम होगी इसका पता चल जाएगा प्रतिदिन आठ ओवर का मैच 4 मैच टीमों के बीच में आयोजित होगा जहाँ उक्त आयोजन में कहीं दर्शक मौजूद।

ग्रामोदय से अभ्युदय मध्यप्रदेश अभियान अंतर्गत जिले में विविध कार्यक्रम सम्पन्न

नरसिंहपुर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप प्रदेशभर में संचालित ग्रामोदय से अभ्युदय मध्यप्रदेश अभियान के अंतर्गत जिले के नेहरू वार्ड, गांधी वार्ड, आमगांव सेक्टर के ग्राम मोहद, ग्राम पंचायत देवनगर नया, लिघारी, डेकरघाट एवं भैंसा हाई स्कूल परिसर में ग्राम विकास पत्रकारिता के अंतर्गत विविध सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य



शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को पत्र हितग्राहियों तक पहुँचाना, सामाजिक समरसता, नशामुक्त समाज की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण तथा नागरिक कर्तव्यों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना रहा। नेहरू वार्ड में आयोजित हुआ

ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान के तहत कार्यक्रम-वार्ड प्रस्फुटन समिति नेहरू वार्ड के स्थानीय झिरना हनुमान मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ के पश्चात पंचदश मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री जयनारायण शर्मा ने सामाजिक समरसता, सद्भाव एवं सामूहिक सहभागिता के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में समिति पदाधिकारी, महिलाएं और नागरिक मौजूद थे। गांधी वार्ड में दिलाई नागरिकों की शपथ- ग्रामोदय से अभ्युदय

अभियान के अंतर्गत गांधी वार्ड में वार्ड उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के डॉ. नागेंद्र सिंह एवं स्वामी निरंजन गंगाधर पालिमंकर जो महाराज की मौजूदगी में सामाजिक जागरूकता, जनभागीदारी, न्यायमूर्ति एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को अपनाने का आह्वान किया गया। साथ ही नागरिकों की शपथ भी दिलाई गई। आमगांव सेक्टर के ग्राम मोहद में जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी- विकासखंड करेली अंतर्गत की ग्राम पंचायत मोहद में ग्राम स्तरीय ग्रामोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सेवानिवृत्त शिक्षक प्रवीण को दी भावभीनी विदाई

बयालीस साल इक्कीस दिनों का रहा यादगार सफर



केंद्र अमझेरा, जिला पंचायत धार मुस्लिम कमेटी अमझेरा, विद्यासभा सरदारपुर, कार्यलय ग्राम पंचायत अमझेरा आदि अभिनंदन पत्रों से स्वागत सम्मान किया गया पत्रों का वाचन आश्विन शर्मा ने किया पंचोली अपने बयालीस साल के सफर में बीस साल तक अमझेरा में बूथ लेवल ऑफिसर रहकर नगर में आदर्श मतदान बूथ की बनाने की शुरुआत की साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में गुरु की महिमा बताई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाये दी, जिला पंचायत सदस्य

गायत्री पुरोहित ने बताया की हमने शिक्षक से अनुशासन के बारे में बहुत कुछ सीखा है, बीओ विष्णु रघुवंशी ने सेवा निवृत्त के बाद के कार्यों को जल्द ही पूरा करने को कहा है नीलाम्बर शर्मा ने बचपन के दिनों को अपने उद्बोधन में रखा साथ ही निरंजन कसेरा ने सेवानिवृत्त का सफर आया है कविता का वाचन किया, बेटी रुची पंचोली ने पापा आप हमारे आदर्श है कविता का वाचन किया कार्यक्रम के अंत में प्रवीण को डोल के साथ आतिशबाजी करके घर तक विदा किया गया जिसमें पूरा माहौल गमगीन हो गया सभी की आँखें नम हो गयी और आसूँ झलकते नजर आये साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तगोवि, जिला पत्रकार अध्यक्ष छोटे शास्त्री कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, अपर कलेक्टर संजीव पांडे, डिप्टी कलेक्टर मेधा पंवार, एसडीएम सलोनी अग्रवाल, नायब महसूलदार सलोनी पटवा, जनजातीय कार्य विभाग सहायक आयुक्त नरोत्तम वरकडे आदि प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रवीण को शुभकामनाये प्रेषित की कार्यक्रम में कैलाश चौधरी, अश्विन दीक्षित सुनील संचेती, सुरेश चंद्र व्यास, कैलाश चंद्र बघेल, सुशिल खडेलवाल, आरपी दोहरे, राजेश शीवास्तव, बीआरसी भंवर, कमल यादव, विजय शर्मा विद्यालय शिक्षक और छात्र छात्राये सहित परिवार के सदस्य मजूद रहे कार्यक्रम का सञ्चालन वैशाली देशमुख ने किया और आभार राघवेंद्र कमरिया ने व्यक्त किया।

उदासीन बड़ा अखाड़ा गौतमपुरा में 16 फरवरी को विशाल भंडारा, संत स्मृति में उमड़ेगा श्रद्धा का सागर



दास जी महाराज का संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति, मानव सेवा और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में समर्पित रहा। उनकी स्मृति में यह आयोजन केवल भंडारा नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का पर्व है।- कार्यक्रम के अंतर्गत विधिवत कन्या पूजन किया जाएगा, जिसके पश्चात श्री चंद्र भगवान को भोग अर्पित किया जाएगा। संत परंपरा के अनुसार प्रभु भोग के उपरांत 16 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें सभी वर्गों के श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करेंगे। इसके पूर्व पवित्र पर्व महाशिवरात्रि (15

फरवरी) के अवसर पर शिवभक्ति के वातावरण में फरियाली खीर की प्रसादी का वितरण किया जाएगा, जिससे संपूर्ण आश्रम परिसर हर-हर महादेव के जयघोष और भक्ति रस से सराबोर रहेगा। महंत श्री पूनम दास महाराज ने क्षेत्र के समस्त धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से इस पुण्य अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में पधारकर संत स्मृति को नमन करने, सेवा भाव में सहभागी बनने और उदासीन परंपरा के मूल्यों को आत्मसात करने की अपील की है। आयोजन को लेकर आश्रम परिसर में तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, शांति व्यवस्था और सेवा कार्यों के लिए स्वयंसेवकों की जिम्मेदारियाँ सुनिश्चित की गई हैं, ताकि यह आयोजन पूर्णतः भक्ति, मर्यादा और आध्यात्मिक शांति के वातावरण में संपन्न हो सके।

नैनपुर प्रशासन की सख्त कार्रवाई: अवैध गतिविधियों पर नकेल, होटल संचालकों को 15 दिनों का अल्टीमेटम

मंडला/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नैनपुर क्षेत्र के होटलों और लॉजों में अनैतिक गतिविधियों, जुआ और आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाओं की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग अब सख्त रुख अपना रहा है। हाल ही में की गई संयुक्त कार्रवाई के तहत कई सख्त होटलों को सील कर दिया गया है। होटल एवं लॉज संचालकों को अहम बैठक एवं विधिक दिशा-निर्देश - एस.डी.एम. नैनपुर श्री आशुतोष ठाकुर एवं एस.डी.ओ.पी. नैनपुर श्री मनीष राज के नेतृत्व में पुलिस थाना परिसर में क्षेत्र के समस्त होटल एवं लॉज संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया



कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान संचालकों को अधिनियमों और प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें सख्त अधिनियम 1867, होटल एंकोमोडेशन एक्ट 1961, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं स्थानीय निकायों द्वारा

प्रशासित नियम एवं सुरक्षा मानक, प्रशासन द्वारा सभी संचालकों को कड़े लहजे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। होटल का विधिवत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्रत्येक आगंतुक का अनिवार्य रूप से आगंतुक पंजी में जानकारी संधारण और आधिकारिक पहचान पत्रों का उचित संधारण। परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों की स्थापना। फायर एनओसी और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन। कर्मचारियों के लिए निर्धारित श्रम कानूनों का अनुसरण। प्रशासन ने सभी आवश्यक सुधार और वैधानिक कार्रवाइयाँ पूर्ण करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन न करने वाले होटल और लॉज संचालकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और संस्थाओं को स्थायी रूप से बंद करने की चेतावनी दी गई है।

इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में बड़ा संकेतरू पशुपालन बना ग्रामीण अर्थव्यवस्था का 'ग्रोथ इंजन'

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने भारतीय कृषि की बदलती तस्वीर को स्पष्ट रूप से सामने रखा है। सर्वे के अनुसार, पशुपालन क्षेत्र अब केवल कृषि का सहायक क्षेत्र नहीं रह गया, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और विकास की धुरी बन चुका है। रिपोर्ट बताती है कि किसानों की आय, कृषि की स्थिरता और भविष्य की विकास रणनीति में पशुपालन की भूमिका तेजी से बढ़ी है।

कृषि संरचना में बड़ा बदलाव- सर्वे के आंकड़े दर्शाते हैं कि कृषि क्षेत्र की कुल 4.6: वृद्धि दर में सबसे बड़ा योगदान पशुपालन और मत्स्य पालन का रहा है, जबकि पारंपरिक फसलों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रही। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि कृषि अब केवल खेतों तक सीमित नहीं,

बल्कि पशुधन आधारित गतिविधियों पर अधिक निर्भर हो रही है। फसल उत्पादन जहां मौसम और जलवायु पर निर्भर होने के कारण अस्थिर और उतार-चढ़ाव वाला रहता है, वहीं पशुपालन क्षेत्र ने 5टु6: की निरंतर और स्थिर वृद्धि दर बनाए रखी है। इससे यह क्षेत्र किसानों के लिए भरोसेमंद आय स्रोत बनकर उभरा है।

किसानों के लिए 'लिक्रिड कैश' का सहारा- सर्वे में उल्लेख है कि पशुपालन किसानों को दैनिक या साप्ताहिक नकद आय प्रदान करता है। दूध, अंडा, मांस और अन्य उत्पादों की नियमित बिक्री से किसानों को निरंतर नकद प्रवाह मिलता है, जिससे वे आकस्मिक जरूरतों और कृषि निवेश को आसानी से संभाल पाते हैं। यह ग्रामीण वित्तीय सुरक्षा का मजबूत आधार बनाता जा

रहा है।

चारे की महंगाई बनी बड़ी चुनौती- रिपोर्ट ने फॉड इम्प्लेशन यानी चारे की बढ़ती कीमतों को भविष्य की गंभीर चुनौती बताया है। सूखे और हरे चारे की कीमतें अनाज से अधिक तेजी से बढ़ी हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन की लागत बढ़ रही है और पशुपालकों के लाभ पर असर पड़ रहा है। सर्वे इस ओर संकेत करता है कि अब केवल पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं, बल्कि चारा प्रबंधन और 'चारा सुरक्षा' पर विशेष नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है।

भविष्य की दिशा- रूढ़िवादीकरण पर जोर- सर्वे के आधार पर यह सुझाव उभरकर सामने आया है कि पशुपालन को केवल बड़े पशुओं तक सीमित न रखकर बकरी पालन और कुकुर पालन जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया जाए। इन उपक्षेत्रों में मांग और वृद्धि दर दूध

क्षेत्र से भी अधिक तेज बताई गई है।

बजट और अवसरचनना की जरूरत- चूंकि पशुपालन कृषि विकास को स्थिर बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, इसलिए शासन स्तर पर कृषि बजट का बड़ा हिस्सा अब पशुपालन अवसरचनना, कोल्ड चेन, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों और मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स (डटन) के सुदृढ़ीकरण पर खर्च करने की ताकिक आवश्यकता सामने आई है।

निकष - इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 स्पष्ट करता है कि पशुपालन विभाग अब खाद्य सुरक्षा, किसानों की स्थिर आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है। आने वाले वर्षों में कृषि विकास की रणनीति पशुधन आधारित गतिविधियों के इर्द-गिर्द ही घूमती नजर आ रही है।

सान्दीपनि विद्यालय टेमला में करियर काउंसलिंग शिविर का समापन

खरगोन/ अंजु त्रिवेदी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। स्थानीय सान्दीपनि विद्यालय टेमला में छात्रों के भविष्य को सही दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अस्सिस्टेंट प्रोफेसर श्री आकाश नेकिया एवं एमपीईबी के अस्सिस्टेंट इंजीनियर श्री रवि बड़े उपस्थित रहे।



मेहनत और सही योजना से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? कार्यक्रम में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री भागीरथ पाटीदार, श्री योगेश पाटीदार, सुश्री साधना सक्सेना एवं श्री

हिस्सा न बनें, बल्कि अपनी रुचि और क्षमता को पहचानकर करियर चुनें। 7वहीं, इंजीनियर श्री बड़े ने तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में अवसरों की चर्चा करते हुए कहा कि, 12वीं के बाद विद्यार्थियों के पास केवल परंपरागत विकल्प ही नहीं, बल्कि कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग और स्टार्टअप के अनगिनत रास्ते खुले हैं। निरंतर

जगदीश मंडलोई की उपस्थिति रही। विशेषज्ञों ने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और समय प्रबंधन के गुर सिखाए। श्री योगेश गढ़े ने अपनी प्रभावी शैली में कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के अंत में श्री सदीप सांगले ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

महिलायें आत्मनिर्भर बनकर देश का नाम रोशन करें - मंत्री श्री कुशवाह

ग्वालियर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सेवा पखवाड़ा एवं विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं उद्यमिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह द्वारा अनूठा एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 135 जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आटा-चक्की मशीनें उपलब्ध कराई गईं। ये सभी ऐसी महिलायें हैं जो अभावों में अपने परिवार के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं। इन सभी को मंत्री श्री कुशवाह ने सीएसआर फंड से आटा-चक्की मशीनें उपलब्ध कराई हैं। 01 फरवरी रविवार को लक्ष्मीगंज धर्मकाटे के सामने स्थित पुराने रेलवे स्टेशन जीवाजीगंज परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ।



कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी

के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश राजौरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, पूर्व विधायक श्री रमेश अग्रवाल, नगर निगम के पूर्व सभापति श्री राकेश माहौर सहित जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे। महिलायें आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार, प्रदेश व देश को मजबूत करें। मंत्री श्री कुशवाह सामाजिक न्याय एवं उद्यमिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नए भारत व समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण का संकल्प लिया है। इसी भावना के साथ आज ग्वालियर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने आटा चक्की मशीनें लेने आई महिलाओं का आह्वान किया कि आप सब आत्मनिर्भर बनकर देश को मजबूत करें, जिससे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप अपना देश विश्वभर का नेतृत्व करें। मंत्री श्री कुशवाह ने महिलाओं से यह भी कहा कि यदि परिवार में कोई नशा

करता हो तो उसे नशे से दूर करने की पहल भी करें। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश राजौरिया ने कहा कि मंत्री श्री कुशवाह ने आटा चक्की उपलब्ध कराकर जरूरतमंद महिलाओं को नई ताकत देने का काम किया है। निश्चित ही इससे महिलायें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि उद्यमिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह द्वारा सीएसआर मद से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी ने भी जनकल्याण व जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह निरंतर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

अंबेडकर भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, सीएमएचओ व डीटीओ ने दिए दिशा-निर्देश

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। आज लटेरी स्थित अंबेडकर भवन में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) तथा जिला क्षय अधिकारी (डीटीओ) सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारी और मैदानी अमला उपस्थित रहा।



बैठक का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन करना तथा फील्ड स्तर पर आ रही चुनौतियों को समीक्षा करना रहा। सीएमएचओ ने सभी कार्यक्रम प्रभारियों से योजनावार प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य,

टीकाकरण, परिवार कल्याण, गैर संचारी रोगों की जांच, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम सहित अन्य प्रमुख योजनाओं में लक्ष्य अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।

जिला क्षय अधिकारी (डीटीओ) ने विशेष रूप से टीबी मरीजों की पहचान, समय पर जांच और नियमित उपचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षय रोग उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के

लिए सदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग बढ़ाई जाए तथा उपचारधीन मरीजों की सतत मॉनिटरिंग की जाए।

बैठक में डेटा रिपोर्टिंग, पोर्टल पर समयबद्ध जानकारी अपडेट करने, फील्ड विजिट बढ़ाने और लाभार्थियों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब मैदानी स्तर पर समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

अंत में उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाएं तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।

राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ 27वां देहदान, स्व. राजाराम पवार ने मानवता को किया अंतिम समर्पण

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। पीड़ित मानवता की सेवा की अनूठी मिशाल रेश करते हुए आज़ाराम कॉलोनी, गांधी नगर विदिशा निवासी स्व. श्री राजाराम पवार का देहदान राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ। श्री विकास पंचेरी फाउंडेशन द्वारा संचालित देहदान, नेत्रदान एवं रक्तदान जागरूकता मिशन के अंतर्गत रविवार को अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, विदिशा में उनके पार्थिव शरीर की देहदान प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस देहदान के साथ मेडिकल कॉलेज में फाउंडेशन के सहयोग से दान किए गए पार्थिव शरीरों की कुल संख्या 27 हो गई है।



स्व. राजाराम पवार एवं उनकी पत्नी श्रीमती शोभा पवार ने 16 जुलाई 2019 को फाउंडेशन के अभियान

से प्रेरित होकर मरणोपरान्त देहदान का संकल्प लिया था। उन्होंने विधिवत वसोहत में उल्लेख किया था कि मृत्यु के पश्चात का पार्थिव शरीर किसी भी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए, ताकि उनका शरीर चिकित्सा शिक्षा और मानव सेवा के कार्य आ सके।

बोते दिनों उनके निधन के उपरांत परिजनों ने समाजसेवी विकास पंचेरी के सहयोग से रविवार को उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। देहदान से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा स्व. पवार के पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अर्पित किया गया तथा पुलिस बल ने 'गाई ऑफ ऑनर' देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

सिरोंज-लटेरी में स्वास्थ्य अमले की संयुक्त बैठक, सुरक्षित प्रसव व शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड पर फोकस

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में विकासखंड सिरोंज एवं लटेरी में एएनएम, सीएचओ, आशा सुपरवाइजर और आशा कार्यकर्ताओं की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुनीत महेश्वरी, जिला क्षय अधिकारी डॉ. समीर किरार तथा दोनों विकासखंडों के खंड चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया गया कि सभी हितग्राहियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता हो। इस उद्देश्य से एक प्रभावी सूचना प्रणाली विकसित करने पर सहमति बनी,

जिसके तहत प्रत्येक माह होने वाले सभी प्रसवों की जानकारी ग्राम स्तर की आशा कार्यकर्ता द्वारा आशा सुपरवाइजर के माध्यम से उच्च स्तर तक नियमित रूप से साझा की जाएगी। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सकेगी।

हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी के निर्देश देते हुए अधिकारियों ने कहा कि ऐसी महिलाओं को समय रहते बर्थ वेटिंग रूम में भर्ती कराया जाए, ताकि सुरक्षित एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जा सके। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को गृह आधारित नवजात देखभाल के सभी भ्रमण शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में विकासखंड स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित

किए जाने की जानकारी दी गई, जो सीधे खंड चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में संचालित होगा। यह कंट्रोल रूम प्रसव, हाई रिस्क मामलों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी में सहायक रहेगा।

इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाए जाएं, ताकि जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सके। बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य अमले ने स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।

किए जाने की जानकारी दी गई, जो सीधे खंड चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में संचालित होगा। यह कंट्रोल रूम प्रसव, हाई रिस्क मामलों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी में सहायक रहेगा।

इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाए जाएं, ताकि जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सके। बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य अमले ने स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए समन्वित रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।

ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हॉर्स पाँवर तक कृषि पंप कनेक्शन मात्र 5 रुपये में

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने किसानों को बंपी राहत देते हुए सिंचाई कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हॉर्स पाँवर तक के ऑनलाइन स्थाई कृषि विद्युत संयोजन के लिए आवेदन शुल्क को मात्र 5 रुपये निर्धारित किया है। यह सुविधा उन मामलों में दी जाएगी, जहाँ विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में भी जारी है। कंपनी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, अब तक प्रचलित व्यवस्था में किसानों से ऑनलाइन आवेदन के लिए 2500 रुपये पंजीयन शुल्क एवं सुरक्षा निधि जमा कराई जा रही थी। नवीन निर्णय के अंतर्गत किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा स्थापित सर्विस लाइन की सुरक्षा नियमों की जांच के उपरांत मात्र 5 रुपये शुल्क में आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जबकि शेष सुरक्षा निधि राशि प्रथम विद्युत बिल में समायोजित कर ली जाएगी। यह निर्णय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम-2022 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है। कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत सुविधा सरल, सुलभ एवं किफायती बनाना है। कंपनी प्रबंधन के निर्देशित किया है कि ऑनलाइन स्थाई कृषि पंप संयोजन जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र पूर्ण की जाए, जिससे किसानों को समय पर लाभ मिल सके।

मार्ग में प्रसव प्रकरण पर सख्त कार्रवाई, जन्मी वाहन अमले सहित स्वास्थ्य कर्मियों पर गिरी गाज

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। पठारी क्षेत्र के ग्राम छपारा-टापरा में 29 जनवरी को एक गर्भवती महिला का मार्ग में प्रसव होने के मामले को कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। कलेक्टर श्री गुप्ता के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार द्वारा जन्मी एक्सप्रेस वाहन चालक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं तथा संबंधित वाहन का जनवरी माह का भुगतान काटे जाने के लिए एमडी एनएचएम को पत्र प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जन्मी एक्सप्रेस एवं 108 वाहन सेवा के जिला समन्वयक श्री तवरेज खान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई हेतु भी एमडी एनएचएम को लिखा गया है। ग्राम छपारा-टापरा में कार्यरत आशा कार्यकर्ता श्रीमती रामवती चिद्धार एवं श्रीमती गीता अहिखार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग पठारी में पदस्थ सीएचओ श्रीमती रीना इनवे तथा सिविदा एएनएम श्रीमती संख्या वर्मा की वार्षिक वेतन वृद्धि दो वर्ष तक रोकने हेतु भी प्रस्ताव भेजा गया है। प्रकरण में पर्यवेक्षणिय जिम्मेदारी के तहत बीएमओ कुर्वाड़ डॉ. प्रमोद दीवान को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जन्मी एक्सप्रेस एवं 108 एंबुलेंस सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, जनोन्मुखी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से विदिशा जिले में दो नए समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। श्री शिवम खरे (मोबाइलरू 8641097356) एवं श्री श्रीकांत (मोबाइलरू 6269903799) 2 फरवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिले की गौशालाओं के सुचारु संचालन के लिए निर्देश जारी

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव द्वारा जिले में संचालित समस्त गौशालाओं के सुचारु एवं प्रभावी संचालन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने गौशालाओं में पशुओं की नियमित देखरेख, टीकाकरण एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी गौशालाओं में गोवंश की टैगिंग (चिह्नकरण) पूर्ण की जाए तथा गोवंश का समय-समय पर टीकाकरण कराया जाए। किसी भी गोवंश की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में जिला प्रशासन, पशु चिकित्सक एवं नजदीकी पशु चिकित्सालय को तत्काल सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। हर साल 02 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व आर्द्रभूमि दिवस हमें उन प्राकृतिक जल क्षेत्रों की याद दिलाता है, जो जीवन, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह दिवस आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की पृष्ठभूमि 02 फरवरी 1971 से जुड़ी है, जब ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह अंतरराष्ट्रीय समझौता आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हुआ। तभी से इस दिन को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

आशा कार्यकर्ता ईमानदारी से निभाएं दायित्व, स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम कड़ी हैं - एसडीएम मनीष जैन

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कुर्वाड़ में रविवार को आशा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण समीक्षा एवं मार्गदर्शन बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना तथा फील्ड स्तर पर कार्यों की प्रगति को समीक्षा करना रहा। बैठक में एसडीएम मनीष जैन ने आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनका कार्य सीधे तौर पर मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने से जुड़ा है। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वे ड्यू लिस्ट के अनुसार घर-घर जाकर पात्र हितग्राहियों की जानकारी अद्यतन रखें तथा संधावित गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान सुनिश्चित करें। उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यह मां और नवजात दोनों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।



ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉ. प्रमोद दीवान ने अपने संबोधन में आशा कार्यकर्ताओं को अपने दायित्वों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सर्वे ड्यू लिस्ट के आधार पर कार्य करने से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों तक समय पर योजनाओं

का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, पोषण परामर्श तथा संस्थागत प्रसव को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

बैठक में मौजूद ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम) ने विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यंत अहम है। उन्होंने समयबद्ध रिपोर्टिंग, सही डेटा संकलन और फील्ड स्तर पर सक्रियता बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने अपने कार्य में आने वाली व्यावहारिक समस्याएं भी अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि फील्ड में बेहतर कार्य के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

बैठक में आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहीं और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।

आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। हर साल 02 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व आर्द्रभूमि दिवस हमें उन प्राकृतिक जल क्षेत्रों की याद दिलाता है, जो जीवन, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह दिवस आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की पृष्ठभूमि 02 फरवरी 1971 से जुड़ी है, जब ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह अंतरराष्ट्रीय समझौता आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हुआ। तभी से इस दिन को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।



आर्द्रभूमियां वे क्षेत्र हैं, जहाँ पानी स्थायी या अस्थायी रूप से मौजूद रहता है। इनमें झीलें, तालाब, नदियाँ, दलदली क्षेत्र, मैंग्रो वन और तटीय क्षेत्र शामिल हैं। ये

क्षेत्र प्राकृतिक जल भंडार के रूप में कार्य करते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आर्द्रभूमियों का महत्व और भी अधिक है। मध्यप्रदेश की बढ़ी आबादी पेयजल, कृषि, मत्स्य पालन और औद्योगिक के लिए आर्द्रभूमियों पर निर्भर है। आर्द्रभूमियाँ भूजल स्तर बनाए रखने, बाढ़ नियंत्रण और सूखे के प्रभाव को कम करने में सहायक होती हैं। साथ ही ये प्रवासी पक्षियों और दुर्लभ वन्य प्रजातियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल भी हैं। वर्तमान में भारत में अनेक आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है, जो संरक्षण के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हालाँकि, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिक प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन आर्द्रभूमियों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। कई पारंपरिक तालाब, झीलें और जल क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं, जिससे जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन की समस्या गहराती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्द्रभूमियों का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। आर्द्रभूमियों में कचरा फेंकने पर रोक, अवैध अतिक्रमण-हटाया, स्थानीय समुदायों को संरक्षण से जोड़ना और जन-जनजातका कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इनके महत्व से अवगत कराना समय की आवश्यकता है।

